/font>

12.44 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OR URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Reported Need for a financial package to Bihar for development works in the State

Title: Dr. Raghuvansh Prasad Singh called the attention of the Ministe r of State in the Ministry of Planning to the need for a financial package to Bihar for developmental works in the state.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : महोदय, मैं योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विाय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :

" राज्य में विकास कार्यों के लिए बिहार को आर्थिक पैकेज तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE

(SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE): Mr. Speaker, Sir, the hon. Members have raised two issues in the Calling Attention Motion (i) grant of an economic package for improvement of the sectors like road connectivity, irrigation and power in the State and (ii) exclusion of backward districts of Bihar under the Backward Districts Initiative component of the Rashtriya Sam Vikas Yojana (RSVY). I would like to clarify the position on the two issues:

I. **Special Plan for Bihar**

Based on wide ranging consultations with the representatives of State Government of Bihar and with the people's representatives of Bihar State, a Special Plan has been formulated for implementation under RSVY with 100 per cent Central Assistance to bring about improvement in sectors like power, road connectivity, irrigation, horticulture, forestry and watershed development. The Central Government has already approved a proposal for investment of Rs. 1,000 crore in identified projects to be implemented in the State of Bihar.

The allocation for the Special Plan for Bihar for the current year is Rs. 500 crore. The schemes which are to be taken up this year include (i) Million Shallow Tubewell Programme, (ii) Restoration of Eastern Gandak Canal in Bihar, (iii) Special projects for Mango, Lichi, Makhana crops and Spices in selected districts of Bihar, (iv) Strengthening of sub-transmission system in Bihar, (v) Development of State Highways in Bihar, (vi) Integrated Forest Management and (vii) Integrated Watershed Development in 8 districts. A sum of Rs. 50 crore has already been released for the Million Shallow Tubewell Programme. Detailed project reports are being prepared and processed in respect of other projects. Steps have also been initiated for selection of implementing agencies and it is expected that implementation of most of the schemes will commence after completion of formalities.

Thus, it may be seen that a Special Plan for Bihar is already under implementation to address all the main concerns raised by the hon. Members.

II. Backward Districts Initiative

The States for which Special Plans had been sanctioned under RSVY have not been included in the Backward Districts Initiative component. However, under the extremist affected districts component of the Backward Districts Initiative, eight districts of Bihar, namely, Aurangabad, Gaya, Jehanabad, Rohtas, Nalanda, Patna, Bhojpur and Kaimur are being covered. In the current year, four districts, namely, Gaya, Jehanabad, Rohtas and Kaimur have been included and the balance will be covered from next year onwards. Under this initiative, each district will get an allocation of Rs. 15 crore per year for three years. Bihar State Government has been requested to forward special district plans for the four districts covered this year for approval of Planning Commission. After approval of the district plans, the first instalment of Rs. 7.50 crore (50 per cent of the annual allocation) will be released for every district.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, हम बिहार की 8 करोड़ 30 लाख महान जनता की ओर से आपके आभारी हैं और हम उनकी ओर से आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने उनकी ज्वलन्त समस्याओं को सदन में उठाने का अवसर दिया।

महोदय, हिसाब-किताब से पता चलता है कि प्रदेश के 42 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे है। प्रदेश का सीडी-रेशो 22 प्रतिशत है, जो देश भर में सबसे कम है। इसके चलते वहां की आर्थिक हालत खराब है। केन्द्रीय सरकार को 3000 करोड़ रुपया सालाना कर्जा चुकाना पड़ता है, क्योंकि केन्द्र की सरकार मुगल की तरह कर्जा वसूल करती है। इसके कारण प्रदेश में रेवेन्यु नहीं बच पाता है और पैसा विकास के कार्यों में नहीं लग पाता है। यह कमिटमेंट है कि बंटवारे से प्रदेश को जो नुकसान

हुआ है, उसकी भरपाई की जाएगी। उसमें सरकार प्रतिबद्ध है। सरकार ने बिहार के बंटवारे से समय घोाणा की थी। मैं एक-एक करके उदाहरण देना चाहूंगा। वहां सड़कों की स्थिति चौपट है। नेशनल हाईवे की स्थिति सबसे ज्यादा चौपट है। राट्रीय राजमार्ग जो भारत सरकार की सड़क होती है, उसकी हालत खराब है। वहां सन् 1996 से लेकर 2003 तक 1929 किलोमीटर सड़क नेशनल हाईवे घोाित की गई थी। राज्य सरकार ने कहा कि उसमें से 1135 किलोमीटर राट्रीय राजमार्ग सड़क की हालत चौपट है और उसके लिए कम से कम 1046 करोड़ रुपए चाहिए। केन्द्रीय भूतल परिवहन विभाग का कहना है कि उसके पास इसके लिए पैसा नहीं है। जहां सड़कों की हालत चौपट है, सड़क में गड्ढे हो गए हैं और उसे बनाने के लिए जो प्रस्ताव आया है, उसके बारे में कहना है कि वित्तीय संकट है, पैसा नहीं है इसलिए इसे नहीं कर पा रहे हैं जैसे नेशनल हाईवे नम्बर 77 जो हाजीपुर, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, सोनबरसा, 17 जिलों से संबंद्ध सड़क है। इसी तरह एनएच 101, 102, 103, 104 और उसके अगल बगल सड़कों की हालत खराब है। सब की हालत चौपट है और सरकार कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है। योजना विभाग बताए कि ऐसी योजना बनाने का क्या मतलब है? आपने स्वीकृति दी और उसके बाद ये सड़कें राट्रीय राजमार्ग घोाित हुईं। आपकी इस बारे में क्या योजना है? 1929 किलोमीटर में से 1135 किलोमीटर सड़कें चौपट हैं। उसके लिए आपने क्या प्रबन्ध किया? राज्य सरकार का एस्टिमेट आपके यहां लम्बित है। सालों-साल पहले आपके भारत सरकार के मंत्रालयों के उच्च अधिकारियों ने वहां का निरीक्षण किया और महसूस किया कि इन सड़कों की हालत खराब है। पैसे के बिना सड़कें नहीं बन रही हैं। इनकी हालत सुधारने के लिए कोई उपाय नहीं किया जा रहा है और न ही राशि का आवंटन हो रहा है। इस काम के लिए एक पैसा नहीं मिला। 1046 करोड़ रुपए में से केवल 77 करोड़ रुपए मिले हैं। इतनी राशि में कैसे काम चलेगा? इसी तरह से पीडबल्यूडी की सड़कें चौपट हैं। कम से कम 1522 किलोमीटर सड़कें चौपट हैं। उसके लिए जब तक 500 करोड़ रुपए नहीं मिलेंगे तब तक उन सड़कों में सुधार होना सम्भव नहीं है। आरईओ की सात हजार किलोमीटर सड़क पक्कीकृत है लेकिन चौपट है। राज्य सरकार के पास उनके सुधार कार्य के लिए एमपी कोटा, एमएलए. कोटा के अलावा दूसरा कोई साधन नहीं है। सात हजार किलोमीटर सड़क के लिए कम से कम साढ़े सात सौ करोड़ रुपए चाहिए। सरकार वचनबद्ध है। इन लोगों ने तय भी किया है कि सड़क, सिंचाई, विद्युत इन सभी मामलों में राट्रीय समविकास योजना से उसकी मदद की जाएगी।

इसी तरह बिजली की हालत है। केन्द्र सरकार ने बिजली में ट्रांसमिशन के लिए राज्य सरकार को सहायता दी है लेकिन अभी तक जेनरेशन में एक पैसे की सहायता नहीं की है। बरौनी थर्मल पावर पुरानी जर्जर हालत में है। मुजफ्फरपुर थर्मल पावर प्लांट की भी यही हालत है। इन दोनों के आधुनिकीकरण के लिए एक करोड़ पर-मेगावाट खर्चा आता है। बरौनी में 320 मेगावाट, मुजफ्फरपुर में 220 मेगावाट â€¦ (व्यवधान) कुल 540 करोड़ रुपए चाहिए। मुजफ्फरपुर में 500 मेगावाट का एक्सटैंशन स्वीकृत है लेकिन पैसे के अभाव में मुजफ्फरपुर थर्मल पावर में उसका कोई विकास नहीं हो रहा है। इस काम के लिए दो हजार करोड़ रुपए चाहिए। जेनरेशन में कम से कम 2540 करोड़ रुपए चाहिए तभी बिजली के क्षेत्र में सुधार हो सकता है। 1999 में इसका शिलान्यास हुआ था। पांच-छः बरस हो गए हैं। इस बीच में थर्मल पावर प्लांट तैयार होना चाहिए था लेकिन वह अभी तक तैयार नहीं हुआ। वहां ढ़िलाई से काम हो रहा है।

बिहार बाढ़, सूखाड़, जल जमाव और कटाव से तबाह होता है। वह चार प्राकृतिक आपदाओं से तबाह होता है। इससे हर साल 1200 से 1500 करोड़ रुपए की तबाही होती है।

अध्यक्ष महोदय, बिहार सुखाड़ और बाढ़ से तबाह है लेकिन भारत सरकार की उपेक्षा से भी तबाह है। मैं सरकार की असलियत सदन को बताना चाहता हूं। न केवल अपने देश की नदियों बल्कि नेपाल से आने वाली अंतर्राट्रीय नदियों से भी बिहार तबाह है। हर साल 1200-1500 करोड़ रुपये की बरबादी होती है। बिना केन्द्र सरकार की मदद के बिहार सरकार के बस में इसका समाधान नहीं हो सकता। दस लाख हैक्टेयर जमीन जल जमाव से ग्रसित रहती है जिससे जल निकासी का कोई उपाय नहीं हो सकता। इसलिये भारत सरकार की सहायता के बिना जल जमाव को खत्म नहीं किया जा सकता। गंगा नदी के कटाव से तबाही है। इसके अलावा बागमती, बूढ़ी गंडक, कोसी नदियों से कटाव होता है। जब भी बिहार सरकार से इस समस्या के समाधान के लिये केन्द्र सरकार को प्रस्ताव जाता है, वह इस पर ध्यान नहीं देती। इस तरह बिहार की उपेक्षा की जाती है।

अध्यक्ष महोदय, वर्ा 1996-97 में भारत सरकार ने एक कमेटी बनायी थी जिसने देश के ऐसे 100 पिछड़े जिलों का चयन किया था जिनका विकास किया जाना था। उन 100 जिलों में से 27 जिले बिहार के थे। अब सरकार ने एक नयी योजना तैयार की है जो देश के 100 पिछड़े जिलों के लिये है लेकिन शर्म और अफसोस की बात है कि इस सूची में बिहार का एक भी पिछड़ा जिला नहीं है। उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के ऐसे 55 जिलों का चयन किया गया जिनमें 8 जिले बिहार के उग्रवाद से प्रभावित हैं। गैर-उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र के ऐसे 7 जिलों का चयन किया गया है, लेकिन उनमें बिहार का एक भी जिला नहीं है।

SHRI T. GOVINDAN (KASARGOD): Sir, I have also given a notice with regard to Regional Rural Bank employees...(*Interruptions*) I am drawing the attention of the hon. Speaker to speak on this...(*Interruptions*)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष महोदय, यह सर्वोच्च पंचायत है और आप सभी को देखने वाले अधिठाता हैं। इस तरह से 8 करोड़ 20 लाख की आबादी वाले पिछड़े राज्य बिहार में से एक जिला भी नहीं लिया गया। जब उग्रवाद और गैर-उग्रवाद क्षेत्र के जिलों को लिया गया, फिर बिहार को क्यो छोड़ दिया गया? क्या भारत सरकार उग्रवाद को बढ़ावा देना चाहती है? इस तरह बिहार के उग्रवाद और गैर-उग्रवाद क्षेत्रों के जिलों को न लेना बिहार के साथ सरासर अन्याय है।

अध्यक्ष महोदय, श्री नीतीश कुमार जी यहां बैठे हुये हैं। उन्हें मालूम है कि उनके नेतृत्व में 60 सांसदों का एक प्रतिनिधिमंडल माननीय प्रधान मंत्री जी से इस संदर्भ में मिलकर ज्ञापन दे चुका है। माननीय प्रधान मंत्री जी से मांग की गई थी कि बिहार को विशेा आर्थिक पैकेज दिया जाये, बिहार का बकाया कर्जा माफ किया जाये.। बिहार पर्यटन और सांस्कृतिक दृटि से दो-तिहाई सदियों का इतिहास रहा है। वह हिन्दुस्तान का भी इतिहास है। भगवान बुद्ध का बौद्ध सर्किट और भगवान महावीर का जैन सर्किट बनाकर पर्यटन के लिये उपाय किये जा सकते हैं। बिहार के साथ भारी उपेक्षा हो रही है। बिहार में सड़क, सिंचाई और बिजली की हालत खराब है। मैंने जो बिन्दु उठाये हैं, सरकार उनकी ओर ध्यान दे।

अध्यक्ष महोदय, माननीय प्रधान मंत्री जी ने देश में नये 5 आई.आई.टी. केन्द्र खोले जाने की घोाणा की है।

13.00 hrs.

बिहार में आई.आई.टी खत्म हो गये, बी.आई.टी. खत्म हो गये। सारे इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में चले गये। आई.आई.टी. की शाखा बिहार में क्यों नहीं होनी चाहिए। ये सारे सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं। इन सारे सवालों पर सरकार ध्यान दे और उस पर कार्रवाई करे। बिहार की जनता और उनकी समस्याएं बहुत नाजुक हैं। बिहार आर्थिक संकट में है, बिहार आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है। इसलिए इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए केन्द्र सरकार भेदभाव भूलकर कार्रवाई करे।

अध्यक्ष महोदय, कृाि पर देश में चालीस रूपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। लेकिन बिहार में नौ रूपये प्रति व्यक्ति खर्च हो रहा है। जब कि नेशनल एवरेज चालीस रुपये प्रति व्यक्ति है। ग्रामीण विकास पर सब राज्यों में पर कैपिटा खर्च बढ़ रहा है, लेकिन बिहार में घट रहा है। अब यह 112 रुपये प्रति व्यक्ति से घटकर 109 रुपये हो गया है। यानी बिहार मे घटोत्तरी हो रही है, इसका क्या कारण है, बिहार के पैसों में कटौती हो रही है। पिछले साल ग्रामीण विकास का 301 करोड़ रुपया काट दिया गया। इसलिए हमारी मांग है कि केन्द्र सरकार बिहार का हिस्सा दे और जो बिहार को पैकेज देने का कमिटमैन्ट है, उस पैकेज में सड़क, बिजली, राट्रीय मार्ग आदि में सुधार के लिए कार्रवाई करे। यही सवाल मैं यहां उठाना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : मेरे पास और तीन नाम हैं - प्रथम श्री राजेश रंजन जी का नाम है, दूसरा श्री रघुनाथ झा जी का नाम है और तीसरा श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी का

नाम है। आप सब लोग नियम जानते हैं कि जो दूसरे बोलने वाले मैम्बर्स हैं, वे केवल मंत्री जी से प्रश्न पूछ सकते हैं। इस पर भााण करने की इस नियम में कोई सुविधा नहीं है।â€¦ (व्यवधान)अभी मैंने पूरा नहीं किया है। लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण विाय पर आप लोग जरूर बोलने चाहेंगे और इसीलिए इस कॉलिंग अटेंशन नोटिस पर लंच के बाद चर्चा शुरू होगी और पहला भााण श्री राजेश रंजन जी का होगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सर, मेरा विशेा अनुमति का मामला है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : सर, आज शुक्रवार है, अभी आप मेरा भााण करवा दीजिए, उसके बाद लंच कर दें।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपको बोलने के लिए केवल दो मिनट मिलेंगे और मैं जानता हूं कि आप दो मिनट में नहीं रुकेंगे, इसलिए लंच के बाद आप बोलें तो आपका भााण अच्छा हो जायेगा। दो मिनट में आप रुकेंगे नहीं और फिर मेरे ऊपर गुस्सा करेंगे, यह नहीं होना चाहिए। आप लंच के बाद शुरू करे, चर्चा हो जायेगी।

श्री लाल मुनी चौबे (बक्सर) : मैं कहना चाहता हूं कि केवल कालिंग अटेंशन बिहार के लिए काफी नहीं है। बिहार को जानना है, वहां की बदहाली को जानना है, इसके लिए केन्द्र दोाी है या वहां की राज्य सरकार दोाी है, इसका फैसला केवल एक कॉलिंग अटेंशन से नहीं होगा। इसके लिए पूरे तीन घंटे रखे जाएं और इस सैशन में ही बिहार के ऊपर डिस्कशन कराया जाए। बिहार के बारे में क्या भूलूं और क्या याद करूं, यह सवाल हमारे सामने है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस पर तीन घंटे का डिस्कशन भी कम हो सकता है।â€¦ (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे एक मिनट सुनिये। बिजनेस एडवायजरी कमेटी में यह विाय आया था और श्री पप्पू यादव जी ने यही मांग की थी कि इस पर तीन घंटे की चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बी.ए.सी. मीटिंग में निर्णय हुआ कि इस विाय पर केवल कॉलिंग अटेन्शन देना चाहिए और इसलिए चर्चा कॉलिंग अटेंशन के माध्यम से आई है। यदि आप चाहते हो तो मैं एक बार फिर से कहूंगा कि सोमवार को बी.ए.सी. की मीटिंग है, वहां यह विाय फिर रखिये, यदि आपके नेता सहमत होंगे तो इस पर चर्चा दी जा सकती है।

श्री लाल मुनी चौबे : सोमवार या मंगलवार को बिहार के सदस्यों की या सदन की राय ले ली जाए, चूंकि बिहार का मामला पूरे देश का मामला बना हुआ है।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : आप मुझे प्रश्न पूछने की इजाजत दे दीजिए, नहीं तो हम लोगों के प्रति बड़ा अन्याय होगा, चूंकि मैं बिहार से हूं।

अध्यक्ष महोदय : इनके बाद दो-तीन मैम्बर्स को एक-एक प्रश्न पूछने की इजाजत दी जायेगी, उनमें पासवान जी आप भी होंगे। लेकिन मैं दूसरे लोगों को केवल प्रश्न पूछने की इजाजत दूंगा भााण करने की इजाजत नहीं दूंगा।

MR. SPEAKER: The House stands adjourned to meet again at 2.00 p.m.

13.04 hrs.

The Lok Sabha then adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

14.04 hrs.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes

past Fourteen of the Clock.

(Mr. Deputy-Speaker *in the Chair*)

CALLING ATTENTION TO MATTER OF

URGENT PUBLIC IMPORTANCE -contd.

Reported Need for a financial package to Bihar for developmental

works in the State

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, let me tell you one thing. The hon. Minister has to go to the other House at 2.30 p.m. As an exception, the hon. Speaker has given me some direction that three or four Members will be allowed to ask some questions. If the hon. Minister is here, then only he will be in a position to reply. But he has got a business in the other House at 2.30 p.m. So, the only thing is that you be brief in your speech.

1405 बजे

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव (पूर्णिया) : उपाध्याक्ष महोदय, हमने सिर्फ सदन में अपना भााण करने के लिए ट्रेन छोड़ दी।

उपाध्यक्ष महोदय : पप्पू यादव जी, मैं केवल आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार का दुर्भाग्य है कि उसका किस परिस्थिति में बंटवारा हुआ और बिहार बंटने के बाद, आज वह जिस मुकाम पर खड़ा है, अगर उस परिस्थिति में जाएंगे, तो हम यही पाएंगे कि बिहार बांटने वाले लोग सदन में भी हैं, सदन के बाहर भी बैठे हैं और सिर्फ राजनीतिक स्वार्थ के लिए बिहार बंट गया। बिहार बंटने के बाद 8.5 करोड़ गरीब लोगों की हालत पर, उनकी परिस्थिति पर कभी भी बिहार में रहने वालों और बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के लोगों ने चिन्ता नहीं की।

महोदय, जब बिहार बंट रहा था, तो केन्द्र सरकार और दिल्ली में बैठे लोगों ने बिहार को विशेा पैकेज देने की घोाणा की जिसे बिहार के बंटने से पहले घोाित किया

जाना था, लेकिन वह घोाणा बिहार बंटने से न पहले की गई और न बिहार बंटने के बाद। बिहार में बेरोजगारी और गरीबी का आलम यह है कि जो उत्तर उन्होंने दिया, उसके अनुसार मैं यहां बताना चाहूंगा कि बिहार में 5334 फैक्ट्रीज थीं। यदि हम शुरू से चलें, डालमियां नगर से, गया से, भागलपुर आ जाएं, सीवान चले जाएं, छपरा चले जाएं, दरभंगा चले जाएं, पेपर मिल, गोपाल गंज सिल्क मिल, दालचीनी मिल, मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि सारी की सारी फैक्ट्रियां बन्द हो गईं। बिहार सरकार में जो को-आपरेटिव संस्थाएं है और जिनके अन्तर्गत 14 और 19 छोटी और बड़ी चीनी मिलें हैं, वे सारी की सारी बन्द हो गई हैं। ऐसी परिस्थिति में बार-बार यह कहा जाता है कि आज बिहार चाहे जिस परिस्थिति में हो, उसे कैसे मजबूत किया जाए और यह बात केन्द्र की ओर से होती है।

महोदय, कई राज्यों को केन्द्र सरकार की ओर से विशेा छूट दी जाती है, लेकिन बिहार विशेा छूट वाले राज्यों में नहीं आता है जबकि देश की आधे से अधिक आबादी यानी 62.3 प्रतिशत निरक्षर हैं। जहां देश का शहरीकरण 27 प्रतिशत है वहां बिहार का शहरीकरण केवल 10 प्रतिशत है और केवल 37 प्रतिशत लोग ही साक्षर हैं। यदि ग्रामीण इलाकों में चले जाइए, तो निरक्षरता की स्थिति और भी ऊपर है। यदि देश के शतप्रतिशत साक्षर वाले राज्य केरल को छोड़ दें, तो देश की आधी आबादी के बराबर 8 हजार 500 करोड़ रुपए की फसल, हर वर्ा जनसंख्या की आबादी के तीन हिस्से के बराबर, बाढ़ से बर्बाद हो जाती है और आज तक आजादी के बाद देश में इस बारे में कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की गई, लेकिन नेपाल और हिमालय से निकलने वाली नदियों से बिहार में आने वाली बाढ़ को रोकने के लिए कोई वृहद् योजना न आज तक बनाई गई और न इस पर चर्चा की गई है। कोसी, कमला, महानन्दा, गंडक, पुनपुन और गंगा आदि कई ऐसी नदियां हैं, जो बड़ी नदियां हैं, लेकिन इनकी बाढ़ से बचाव के लिए कोई चिन्ता नहीं की गई।

महोदय, जो सबसे ज्यादा जरूरत है उस तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। वहां आठ जिलों की घोाणा कर दी कि वे टैररिस्ट्स इलाके हैं, लेकिन कभी आपने यह नहीं सोचा कि उत्तर बिहार में 18-19 और जिले हैं, मध्य बिहार के जिले हैं, दक्षिण बिहार के जिले हैं, वे पूरी तरह से सुखाड़ में हैं।

हम सात महीने बाढ़ में रहते हैं और पांच महीने सुखाड़ में रहते हैं।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक क्लेरीफिकेटरी प्रश्न पूछ सकते हैं, अगर भााण करेंगे तो दूसरे किसी को चांस नहीं मिलेगा।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, मैं लीची, आम, केला, जूट, ईख और मखाना के बारे में कहना चाहता हूं, देश की 25 प्रतिशत चीनी का बिहार में उत्पादन होता है। मंत्री जी, मैं आपको बता दूं कि सनगंज में कम से कम सौ ऐसे चाय के बागान हैं, जहां यदि आप चाय की बागानों के लिए किसी फैक्ट्री की व्यवस्था करते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था करते हैं तो किशनगंज का इलाका अपने पर आत्मनिर्भर होगा। जूट का इलाका, पूर्णियां का किशनगंजâ€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, ये सारा खुलासा कर दिया है। आप फाइनेंशियल डेवलपमेंट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या चाहते हैं, ये बताएं?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मंत्री जी, मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि कटिहार की जूट मिल, बनमनखी और मधुबनी की चीनी मिल या इस तरह की जितनी चीनी मिले हैं, सहरसा और दरभंगा की पेपर मिल, इनके लिए आपने यहां से क्या योजना बनाई है? मैं मानता हूं कि भारत सरकार ने कम पैसे नहीं दिए - चाहे आरएफ में हों या प्रधानमंत्री सड़क योजना हो। मैं जानता हूं कि वहां से भारत सरकार का पैसा लौट जाता है और यह भी मैं मानता हूं कि आज प्रधानमंत्री सड़क योजना का तीन-चार बार दूसरे राज्यों में पैसा गया, लेकिन बिहार में आप एक बार भी पूरा पैसा नहीं भेज सके, इसका क्या कारण है? इस तरह का व्यवहार क्यों किया जाता है, आपने अभी तक उन्हें पूरा पैसा क्यों नहीं भेजा? आपने अन्य राज्यों में दो-तीन-चार बार पैसा भेजा और बिहार में एक बार भी नहीं भेजा।

महोदय, मेरा आग्रह है कि यदि आप बिहार को सुदृढ़ करना चाहते हैं तो उन्हें विशेा छूट दीजिए। बरौनी और मुजफ्फरपुर का जो विद्युत थर्मल पावर है उसे नयी तकनीकी में और डेवलप करके वृहद करिए। यदि इससे भी ज्यादा उसे सुंदर करना चाहते हैं तो जो किसान का बिहार में ऋण है, जब देवेगौड़ा जी प्रधानमंत्री बने तो विशेा पैकेज कर्नाटक को मिला और गुजराल जी बने तो पंजाब को मिला। जो पंजाब देश में सबसे ऊपर है। वहां तीन नदियां हैं और वह सबसे ऊपर है, हम सौ नदियों वाले सबसे नीचे हैं, 32वें स्थान पर हैं। गुजराल साहब बिहार से बने, लेकिन पैकेज पंजाब को मिला। देवेगौड़ा जी को किंग मेकर बनाने वाले बिहार वाले हैं और पैकेज कर्नाटक को मिल गया। बिहार सरकार कहती है कि बिहार में कुछ नहीं है तो मेरा कहना है कि बिहार की सरकार को बिहार छोड़ कर केन्द्र के सुपुर्द कर देना चाहिए। ये कहते हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, बिजली और रोड नहीं है। मंत्री जी, जब तक दस हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं होगा तब तक बिहार के लोग और वहां का गांव सुंदर नहीं हो पाएगा। एनएच में पैसा देने की बात हो रही है, आप उन्हें लिखिए, मैं आपसे लिखवाना चाहता हूं।â€¦ (व्यवधान)

मैं एनएच के बारे में बताना चाहता हूं, किशनगंज से पटना, भाया पूर्णियां, खगड़िया होते हुए,â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : यादव जी, आपके अन्य साथियों को भी प्रश्न पूछने हैं, अब आप समाप्त कीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, मेरा बिहार के विशेा पैकेज से मतलब है, बिहार जिस परिस्थिति और हालात में दूसरे से 32वें स्थान पर चला गया है, उसे उस हालात में लाने के लिए अगर राज्य सरकार कुछ नहीं करती तो मेरा केन्द्र से आग्रह है कि आप विशेा पैकेज के रूप में सारी फैक्ट्रियों को ले लीजिए। कृाि पर आधारित जो लघु, कुटीर उद्योग हैं, बिग और स्माल इंडस्ट्रिज़ हैं, उनका आप पूरा मूल्यांकन करिए।वह मूल्यांकन करने के बाद बिहार में कैसे रोजगार डवलप हो, कैसे वहां के मजदूर बाहर न जायें और बाहर जाने की जहां तक बात है, छात्र बाहर नहीं जायें, इसकी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, यह आपको तय करना पड़ेगा। मेरा आपसे आग्रह है, यहां बिहार के नीतीश जी बैठे हैं, ये रेल मंत्रालय में है, दूसरे लोग भी हैं, सभी लोग हैं, आपने एक भाग में बहुत काम किया, लेकिन उसकी और जो परिस्थितियां हैं, रोजगार की जो परिस्थितियां हैं, वहां से विद्यार्थी, बिहार के नौजवान बाहर जा रहे हैं।...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब किसी को भी चांस मिलने की उम्मीद नहीं है।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उनके लिए रोजगार कैसे पैदा हो, सबसे ज्यादा केन्द्र को वहां रोजगार पैदा करने के लिए कोई नई ताकत, कोई नई फैक्टरी, बन्द पड़ी फैक्टरी का काम करना चाहिए। मैं अन्तिम बात बोल रहा हूं।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अन्तिम बात नहीं, क्लैरीफिकेटरी क्वश्चन पूछना है। आप भााण कर रहे हैं, इससे सब चांस नहीं मिलेगा। मिनिस्टर अपर हाउस में चले जाएंगे। अब आप सवाल पूछिये।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं वही कर रहा है, मैं अन्तिम बात बोल रहा हूं। बिहार बंटने के बाद वहां पर एक टैक्नीकल कालेज नहीं है। क्या कोई आई.आई.टी., आई.टी.आई. या कोई ऐसा टैक्नीकल कालेज, जो कर्नाटक में 40 से ऊपर हैं और जगह 60 हैं, कहीं 100 हैं, कहीं 200 हैं, क्या बिहार में भी आपकी ऐसी योजना है, क्या पटना को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की योजना है?

उपाध्यक्ष महोदय : यदि योजना है तो आप बता दीजिए।

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : क्या आप नये टैक्नीकल कालेज खोलेंगे। क्या जैन और बौद्ध का जो बिहार है, वैशाली राजगीर में से आप सिर्फ राजगीर और बोधगया एक ऐसी जगह है, यदि भारत सरकार उसे सुसज्जित और सुन्दर बना दे तो पूरे बिहार की रायल्टी दो जगह से दी जा सकती है। मैं इनसे अन्त में कहना चाहता हूं कि चाहे वैशाली की धरती हो या शेरशाह सूरी की हो या वीर कुंवर सिंह जी की हो, दुनिया के सभी देशों के बुद्धिस्ट बिहार आते हैं। यदि आप सिर्फ उसे पर्यटन स्थल के रूप में विश्व के पैमाने पर विक्रमशिला और नालन्दा को पर्यटन स्थल के रूप में डवलप कर देते हैं तो बिहार सरकार

â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : भााण के बदल मिनिस्टर से एक सवाल पूछिये। यह आप क्या कर रहे हैं?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मैं वही कह रहा हूं। क्या आप उसे करना चाहते हैं और यदि करना चाहते हैं तो इससे निश्चित रूप से बिहार का हित होगा।

मैं इन्हीं शब्दों के साथ कहना चाहता हूं कि आप किसान का ऋण माफ करें, वहां रोजगार डवलप करें, साथ-साथ बिहार को विशेा पैकेज देकर सिंचाई, जल, सड़क और फैक्टरियों के मामले में वृहद करें, यही मेरा आपसे आग्रह है। बिजली और सड़कों को जितना सुन्दर हो सके, वह आप करने की कृपा करें।

*(Interruptions) â€¦**

उपाध्यक्ष महोदय : इसके बाद कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जायेगा।

---

* Not Recorded

श्री रघुनाथ झा (गोपालगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी के उत्तर को देखा है और उन्होंने जो पढ़ा, उसे भी ध्यान से सुना। मैं ऐसा मानता हूं कि प्र ाथम पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक बिहार के साथ केन्द्र की सरकार ने घोर उपेक्षा की है। जब योजना आयोग का गठन हुआ था और देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू ने उस प्रथम बैठक का उद्घाटन करते हुए यह कहा था कि योजना आयोग जहां देश के त्वरित और क्रमिक विकास करने के लिए योजनाओं के माध्मय से आगे बढ़ेगी, वहां देश में जो रीजनल इम्बेलेंसिज हैं, क्षेत्रीय असमानता है, उसे दूर करने का काम करेगी। लेकिन पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर आज तक आप अगर देखेंगे तो बिहार के साथ पूरे तौर पर भेदभाव किया गया। जब बिहार और झारखण्ड एक साथ थे, उस समय भी हमारी रायल्टी हमें नहीं दी गई, मूल्य के साथ उसे नहीं जोड़ा गया।

हमारे यहां जो बड़े-बड़े कल-कारखाने रहे, उनमें से किसी का हैडक्वार्टर कलकत्ता, किसी का हैडक्वार्टर मुम्बई और किसी का हैडक्वार्टर दिल्ली में रहा, जिसके चलते हमारे प्रदेश का सेल्स टैक्स और कन्साइनमेंट टैक्स नहीं मिल पाया। हमारे यहां नेपाल से आने वाली नदियों से नुकसान होता है।

बिहार का बहुत बड़ा भाग, उत्तर प्रदेश का कुछ हिस्सा नेपाल से आने वाले नदियों से प्रभावित होता है। उससे होने वाले नुकसान के कारण हमारा इलाका और पूरा उत्तर बिहार आज गरीबी की गर्द में है। हमारा जो इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, चाहे सड़क हो, स्कूल भवन हो, मकान हो जमीन हो या खेती हो, वे सब बर्बाद होते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार ने उसे रोकने के लिए कोई कारगर कदम नहीं उठाया है।

हम माननीय मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि क्या उनको पता है कि बिहार में आने वाली 90 प्रतिशत नदियां नेपाल से निकलती हैं, चाहे वह गंगा हो, कोसी हो, बूढ़ी गंडक हो, बागमती हो, कमला बालान हो आदि जितनी भी नदियां हैं, वे अदवारा समूह की नदियां हैं। उन नदियों से बिहार के बड़े भू-भाग को और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को नुकसान होता है। आप उसकी भरपाई करने के लिए नेपाल सरकार से बात करें। नेपाल सरकार से वार्ता करके आप कोई कारगर उपाय कीजिए जिससे बिहार इस गरीबी और गर्द से अपने को निकाल सके, अन्यथा जैसे बड़े-बड़े साइक्लोन या भूकम्प आने पर आप दूसरे राज्य को केन्द्रीय सहायता देते हैं, उसी तरह से बाढ़ से होने वाली क्षति की भरपाई केन्द्र सरकार को अपनी तरफ से उठानी चाहिए ताकि बिहार अपने पैरों पर खड़ा हो सके।

माननीय रेल मंत्री जी यहां बैठे हुए हैं। जब बिहार का बंटवारा हो रहा था, इसी सदन में चर्चा हुई थी, उस समय हमारे साथी श्री प्रभुनाथ सिंह जी उसका विरोध कर रहे थे। हम लोग भी उसके विरोध में थे। हम इस बात को मानते हैं कि केन्द्र और बिहार की दोनों सरकारें ईक्वल रूप से बिहार को बांटने में जवाबदेह हैं। बिहार बंट गया और बंटने के बाद माननीय रेल मंत्री जी ने बिहार के तमाम मंत्रियों, जो केन्द्र सरकार में हैं, उनको और बिहार के सांसदों को बुलाने का काम किया, बिहार के ि वकास के लिए कि बिहार कैसे अपने पैरों पर खड़ा हो, उनसे यह बात की। हमें जितना रेवन्यू मिलता था, वह झारखंड में चला गया और आबादी हमारे पास रह गयी। सारा नुकसान हमको उठाना पड़ा। माननीय रेल मंत्री जी ने एक मेमोरेंडम तैयार किया और उसे लेकर वे आदरणीय प्रधान मंत्री जी से मिले। इसी सदन में माननीय गृह मंत्री जी ने घोाणा की। माननीय प्रधान मंत्री जी ने हम लोगों के साथ बहुत अच्छे ढंग से बात की और कहा कि हम लोग हर तरह से इसमें मदद करेंगे लेकिन मदद के नाम पर बिहार को शून्य मिला।

बिहार के बारे में भले ही दूसरी जगह तरह-तरह की भ्रान्तियां पैदा होती हों लेकिन बिहार को देखने के लिए, बिहार को समझने के लिए अगर केन्द्र सरकार नहीं सोचेगी तो कुछ नहीं होगा। अभी पप्पू यादव जी ने दूसरे राज्यों का जिक्र किया। गुजराल जी ने पंजाब के बारे में यही किया। सबसे नम्बर वन पर रहने वाले हरियाणा और पंजाब का कर्जा आप माफ करते हैं लेकिन बिहार जो सबसे दरिद्र है और जिसे अंतर्राट्रीय नदियों से नुकसान उठाना पड़ता है, प्रति वा हम उसे दरिद्र करते हैं। दिन रात कर्पूरी ठाकुर जी याद आते हैं चाहे वे विपक्ष के नेता रहे हों या मुख्यमंत्री रहे हों, वे बराबर कहते रहे कि जब तक केन्द्र सरकार और नेपाल सरकार कारगर ढंग से वार्ता करके नेपाल से आने वाली नदियों से जो हमारा नुकसान होता है, उसे रोकने का काम नहीं करेगी तब तक बिहार से गरीबी दूर नहीं होगी। लेकिन आज तक बिहार की हालत वही है। हमारे यहां बक्सर से लेकर फरक्का तक गंगा नदी के दोनों किनारे में सैंकड़ों गांव कटकर गंगा में विलीन हो गये। हजारों एकड़ जमीन ि वलीन होती है। दूसरी नदियों के साथ भी यही हो रहा है।

हम जानना चाहते हैं कि इसे रोकने के लिए आपने क्या काम किया है ? माननीय मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में मोकामा टाल, बड़हिया टाल, लक्खीसराय टाल में सालों भर पानी रहता है। वहां फसल मुश्किल से होती है। हमारा बहुत बड़ा भू-भाग वाटर लागिंग से प्रभावित होता है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने उससे निजात दिलाने के लिए कोई योजना बनाई है या नहीं ? इस समय बूढ़ी गंडक के तटबंध की आप मरम्मत करने जा रहे हैं। नदी में सिलटेशन हो गया। नदी काफी ऊंची हो गयी। हर साल बाढ़ आ रही है। आप इसे फेज वाइस करके बिहार को नहीं बचा सकते।

अगर उसे पूरे तौर पर बचाना है तो आपको नदियों पर तटबंध बनाना चाहिए।

यह ठीक है कि बिजली के क्षेत्र में भारत सरकार ने पावर ग्रिड कार्पोरेशन को ट्रांसमिशन ठीक करने का काम दिया है। उसके लिए हम बधाई देना चाहते हैं। राजनाथ जी के समय में जब नीतिश जी भूतल परिवहन मंत्री थे, उस समय बिहार में जो राट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हुए, रघुवंश बाबू कह रहे थे कि वे पीडब्ल्यूडी से भी बदतर हालत में हैं। आखिर आपने स्वीकृति दी है तो उसे कौन बनाएगा, कौन चलाएगा। हमारे यहां मोहम्मदपुर से मलमलिया होकर प्रभुनाथ सिंह जी के क्षेत्र छपरा तक एक

रोड जाती है - एनएच-101, जिस पर 5-7 किलोमीटर मोहम्मदपुर से काफी गड्ढे हैं और उसी से सिदबलिया शुगर फैक्ट्री में किसान अपना गन्ना ले जाते हैं। उनको गन्ना ले जाने में कठिनाई हो रही है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अब आप सवाल पूछिए।

श्री रघुनाथ झा : हम जानना चाहते हैं कि नेपाल से आने वाली नदियों और उनसे होने वाले कटाव, वाटर लॉगिंग रोकने की सरकार के पास कोई योजना है या नहीं। दूसरा प्रश्न है कि जितने राट्रीय राजमार्ग स्वीकृत हए, क्या आप टाइम लिमिट फिक्स करके पैसा देकर उन्हें बनवाना चाहते हैं या नहीं। तीसरे, आपने किस तरह ट्रांसमिशन का काम दिया है लेकिन ग्रामीण विद्युतीकरण और विद्युत के दूसरे क्षेत्रों में जनरेशन के लिए पैसा देना चाहते हैं या नहीं। हमारे यहां जो जल जमाव है, जो ताल इलाका है और सुखाड़ इलाका है, उसके लिए कुछ करना चाहते हैं या नहीं।

इन्होंने बहुत चालाकी से बिहार के कुछ जिलों को जोड़ने का काम किया। जब देश के सौ जिले जोड़े गए, हमारी पौपुलेशन के हिसाब से आपने हमारा हिस्सा क्यों काट दिया। हमें उग्रवादी इलाका समझ कर सिर्फ आठ जिले जोड़े। आप सरकार चला रहे हैं, आपको जानकारी है, उत्तर बिहार का एक भी जिला - पूर्वी और पश्चिमी चम्पारन, शिवहर, सीतामढ़ी से लेकर किशनगंज तक कोई भी ऐसा जिला नहीं है जो माओवादी इंसर्जेंसी से प्रभावित नहीं है। माओवादियों, नक्सलवादियों ने कितने थाने लूट लिए। आपने उन जिलों को इसमें क्यों नहीं सम्मिलित किया। रेलवे लाइन भी उन्होंने उड़ा दी। आपकी नजर में आने के बाद भी आपने उसे रोकने का काम नहीं किया। आप यह काम कब तक करना चाहते हैं, बिहार के लोग यह बात स्पट रूप से जानना चाहते हैं। आप आज बताएं कि आप उन्हें कब तक ठीक करेंगे।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने आज बिहार के आर्थिक पैकेज, सड़क, पानी और बिजली के संदर्भ में विचार व्यक्त किए। यह विाय बहुत ही मौलिक और महत्वपूर्ण है। मैंने इस बात का जिक्र इसलिए किया क्योंकि यह एक ऐतिहासिक दुखद बात है। आज से ही नहीं, चाहे किसी का भी शासन रहा हो, केन्द्र के जरिए बिहार की लगातार घोर उपेक्षा होती रही है। यह कोई नई बात नहीं है। मैं इस बारे में तर्क देना चाहता हूँ, प्रमाण देना चाहता हूं कि बिहार की उपेक्षा कैसे-कैसे हुई। बिहार को जो बजट का आकार मिलता रहा है, वह किस बेसिस पर मिलता है। वह on the basis of internal resources मिलता रहा है। आंतरिक संसाधन मोबीलाइज़ करने की कोई क्षमता बिहार में नहीं बची। खास तौर से जब बिहार का बंटवारा हो गया, झारखंड अलग हो गया, उस समय भी हमने इस सदन में घोर आपत्ति व्यक्त की थी और चालीस मिनट तक बिल को रोका था कि यह आने वाले दिनों में बिहार की फटेहाली और गरीबी को और बढ़ाएगा। आज बिहार की हालत नार्थ-ईस्ट से भी ज्यादा खराब हो गई है। हम नार्थ-ईस्ट की हालत के बारे में संसद में चिन्ता करते रहते हैं। लेकिन अभी बिहार की जो ज्वलंत समस्या है, वह बहुत ही दुखदायी है। मैंने इसलिए आपका ध्यान इस ओर दिलाया है कि ऐतिहासिक तौर पर पहले से ही बिहार के साथ यही व्यवहार केन्द्र के जरिए होता रहा है। बिहार को बजट का जो आकार दिया जाता है, योजना आयोग के राज्य मंत्री यहां बैठे हुए हैं, वे उसका यही आधार देना चाहते हैं कि बिहार में इंटरनल रिसोर्सेज़ कितने हैं। झा जी ने ठीक कहा कि झारखण्ड में सारा खनिज रायल्टी चला गया ।

जो था, वह झारखंड में चला गया। रघुवंश बाबू ने सवाल उठाया था। इंजीनियरिंग कॉलेज झारखंड में चला गया। सब कुछ झारखंड में चला गया। गाडगिल का जो पुराना एतिहासिक फॉर्मूला है, उसको बदले बिना बिहार का विकास नहीं हो सकता क्योंकि इसके तहत जो बजट का आकार मिलता है, वह इंटरनल रिसोर्सेज मॉबिलाइजेशन के आधार पर मिलता है। जब हमारी इंटरनल रिसोर्सेज है ही नहीं हैं तो हम मौबिलाइज क्या करेंगे? मैं सुझाव देना चाहता हूं और सरकार से मांग करना चाहता हूं तथा केन्द्र सरकार से कहना चाहता हूं कि जब तक बिहार के बजट का आकार on the basis of the needs of the people of the concerned State, that is, Bihar नहीं होगा क्योंकिवहां 52 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। जब तक बिहार के प्लान का आकार on the basis of poverty, on the basis of population, and on the basis of the needs of the State नहीं होगा, तब तक बिहार सात जन्म में विकास नहीं कर सकता। जो बैंकिंग है,â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, अन्य माननीय सदस्यों को भी आपने मौका दिया है, हमें भी थोड़ा और समय दीजिए। यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। बिहार के 8 जिले उग्रवाद में चुने गये हैं। 36 जिले उग्रवाद में चुन लिए जाएंगे, यह परिस्थिति भी वहा पैदा हो सकती है। उग्रवाद को बढ़ाने का काम कम से कम केन्द्र सरकार न करे।â€¦ (व्यवधान)मेरा दूसरा सवाल है कि जो पूंजी का वितरण होता है, जो पूंजी का निवेश होता है, बैंक में सी.डी.रेशियो देखा जाए चाहे कोई वित्तीय संस्था बिहार में हो, उसका, उन सभी बैकों का सी.डी. रेशियो 15 प्रतिशत है। अनुपात किसी का 16 प्रतिशत है, किसी का 17 प्रतिशत भी है लेकिन अनुपात रेशियो 15 प्रतिशत ही बिहार में जमाकर्ता के द्वारा जो बैंक में वहीं की जनता जमा करती है, उसका वहां खर्च मात्र 15 प्रतिशत होता है और 85 प्रतिशत पैसा बड़े-बड़े महानगर चाहे वह महाराट्र हो, मुम्बई हो, चाहे कोलकाता हो, वहां चला जाता है। इस प्रकार से बिहार का विकास कैसे होगा ? एक हिस्टोरिकल बात कही है और मैं जो बात कह रहा हूं, उसको प्रमाणित कर सकता हूं। इसीलिए मेरा तर्क है कि आरबीआई की गाइडलाइन्स कृाि का विकास करने के लिए है कि संबंधित राज्य में तीस से चालीस प्रतिशत पैसा उसी राज्य में खर्च होना चाहिए। बिहार में केवल 15 प्रतिशत होता है और सब पैसा बाहर चला जाता है। प्रधान मंत्री योजना का तो बैंक को सहयोग है ही नहीं है, निल है। तीसरी बात मैं एन.एच. से संबंधित कहना चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : नियम 197 के मुताबिक आप एक ही सवाल पूछ सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय,वहां एन.एच. की हालत इतनी जर्जर है कि एन.एच.104 जो है, भीखामोड़ है, जो माननीय सदस्य का गृह क्षेत्र है, वहां सीतामढ़ी से लेकर जयनगर- मधुबनी जिला अर्न्तगत जयनगर-लदनिया-लौकहाँ-लौकही-नरहिया तक चला जाता है। इस रोड की इतनी हालत खराब है कि भारत नेपाल सीमा पर यह एन.एच. है और जब राज्य सरकार का एन.एच. कंवर्ट कर गया, केन्द्र सरकार ने स्वीकृत कर दिया तो उसमें एक पैसा उन्होंने रिलीज नहीं किया।

जहां तक बाढ़ और सुखाड़ का मामला है, जल-जमाव और कटाव का मामला है, उत्तर भारत से हम लोग आते हैं। आपको स्मरण होगा कि इसी सदन में दो दिन तक इस पर सवाल उठता रहा था जब हम पर लाठीचार्ज हुआ था और हमारे सैकड़ों साथी घायल हुए थे और जब 9 दिसम्बर 2002 को संसद मार्च हुआ था तब बहुत जबर्दस्त रूप में सरकार आई थी कि हम कुछ करेंगे और क्या हुआ ? मैं बताना चाहता हूं। जो हाइ-लैवल डैम उत्तर बिहार में बनना था, चाहे कमला हो या कोसी हो और गंडक नदी हो, वहां बागमती नदी पर हाइ-लैवल डैम बनाने के लए ज्वाइंट-प्रोजेक्ट कार्यालय सात जगह खुलना था और नेपाल में सन् 2000 में ही भारत नेपाल का समझौता हुआ था कि फंडिंग का काम भारत करेगा और वहां ज्वाइंट प्रोजेक्ट कार्यालय खुलकर मल्टी-पर्पज हाइ-लैवल डैम बनेगा जिससे पन बिजली भी पैदा होगी। एक अकेले कोसी नदी से 3300 मेगावॉट बिजली पैदा हो सकती है।

चूंकि हमारा जो ध्यानार्काण है, उसमें बिजली का भी सवाल है। सड़क, पानी और बिजली का सवाल है। पानी और बिजली पर हम बोलकर खत्म करेंगे। पानी की हालत क्या है कि वहां न बाढ़ पर नियंत्रण है और करोड़ों की फसल, हर साल उत्तर बिहार में 8 करोड़ 30 लाख में से 6 करोड़ लोग बाढ़ से प्रभावित रहते हैं और 2 करोड़ 30 लाख लोग सुखाड़ से प्रभावित रहते हैं।

दक्षिण बिहार में सुखाड़ और उत्तर बिहार में बाढ़ से लोग प्रभावित रहते हैं। छः महीने बाढ़ और छः महीने सुखाड़ बिहार की यही नियति बन गई है। बिहार में पानी की

समस्या का हल निकाला जा सकता है।

MR. DEPUTY-SPEAKER: The next item on the agenda − Discussion under Rule 193 − also concerns Bihar. Do not exhaust yourself now.

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। जब बिहार में नेपाल की सहायता से हाइड्रो बिजली पैदा होगी तो सस्ती दर पर लोगों को बिजली मिल सकती है। पिछले सत्र में कहा गया था कि बिहार के लिए डीपीआर की 24,600 करोड़ रुपए की योजना बनाई जाएगी। उसमें अभी तक कोई प्रगति नहीं हुई है। जब तक बिहार में सुखाड़ और बाढ़ का स्थाई समाधान नहीं होगा, उत्तर बिहार के छः करोड़ लोगों के लिए कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करेंगे, वह ध्वस्त हो जाएगा। वहां हर साल करोड़ों रुपए की फसल बर्बाद हो जाती है।

डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम पर हर साल केन्द्र से पांच हजार करोड़ रुपए की राहत और पांच हजार करोड़ रुपए नकदी के रूप में बांटे जाते हैं। लेकिन या सारा पैसा बेकार चला जाता है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि आप बजाय हर साल वहां पैसा दें, इसका स्थाई समाधान निकाल कर बाढ़ को रोकने का प्रयास करें। सरकार क्यों हर साल डिसास्टर मैनेजमेंट के नाम पर हम लोगों को रिलीफ बांटती है और देश में पुरूार्थी बनने से हमें समाप्त किया जा रहा है। हर साल बाढ़ और सुखाड़ के नाम पर हम लोग भीख नहीं चाहते, हम इस तरह से हर साल रिलीफ नहीं चाहते। हम यहां हर साल बाढ़ और सुखाड़ पर चर्चा करते हैं, जो कि हम नहीं करना चाहते। हमें सरकार की ओर से आर्थिक पैकेज दिया जाए और इन समस्याओं का स्थाई समाधान किया जाए। आपने कहा था कि बिहार को आर्थिक पैकेज दिया जाएगा, वह क्यों नहीं दिया जा रहा है, इसको स्पट किया जाए।

उत्तर बिहार में एकमात्र कृाि ही जीविका का साधन है। लेकिन सारी जमीन पानी से डूबी रहती है, जल जमाव रहता है। फसलों का लाभकारी मूल्य नहीं मिल पाता है। वहां सारी 15 चीनी मिलें बंद हो गई हैं। इस तरह से सारा आर्थिक जरिया समाप्त हो गया है, कुछ बचा नहीं है। रोजगार का कोई साधन नहीं है। लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है। यही कारण है कि बिहार आज सबसे गरीब राज्यों की सूची में अव्वल नम्बर पर गिना जाता है। वहां मखाना की खेती हो सकती है, एग्रीकल्चर में काफी सम्भावनाएं हैं, तालाबों में परम्परागत तरीके से मछली पालन किया जा सकता है। इसके अलावा फलों में आम, लीची आदि की फसलें उगा कर, प्रोसेसिंग करके उस क्षेत्र को विकसित किया जा सकता है। लेकिन यह कुछ नहीं हो रहा है।

अभी सरकार की तरफ से पूरे देश के 100 पिछड़े जिलों की सूची बनाई गई। उसमें बिहार का एक भी जिला शामिल नहीं है। यह जरूर है कि उग्रवादी जिलों के रूप में बिहार के कुछ जिले शामिल किए गए हैं और कहा गया है कि 50 करोड़ रुपए देकर उनको विकसित किया जाएगा। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश भर के 100 पिछड़े जिलों की सूची बनाते समय ऐसा कौन सा मानदंड बनाया गया जिससे बिहार का एक भी जिला उसमें नहीं लिया गया ? उग्रवादी जिलों के बारे में आप कहते हैं कि कुछ पैसा दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि उग्रवाद को बढ़ाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हम उग्रवादी बनें तो आप पैसा देंगे। लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें तो आप कहेंगे कि हम पैसा नहीं देंगे, आप कम्पीट नहीं करते। क्या उग्रवाद मानदंड बन गया है कि जहां उग्रवादी गतिविधियां होंगी, उसको पिछड़ा जिला मानेंगे ? सारे देश के लिए एक मानदंड और बिहार के लिए दूसरा मानदंड अपनाया जा रहा है। पूरे देश में बैकवर्डनैस है, उसका अलग पैरामीटर बनाया गया है, लेकिन हमारे यहां उग्रवाद को पैरामीटर बना दिया गया है। केन्द्र की ओर सेयह दोहरा मानदंड नहीं होना चाहिए। केन्द्र की ओर से ऐतिहासिक रूप से बिहार की उपेक्षा की जाती रही है। इससे बिहार रसातल में जा रहा है। इसलिए सरकार संवेदनशील होकर इस पर विचार करे और बिहार को आर्थिक पैकेज देने की तुरंत घोाणा करें। इसके अलावा बाढ़ और सुखाड़ के लिए 24,600 करोड़ रुपए का डीपीआर तुरंत रिलीज करे और इस काम में तेजी लाकर इसको अंजाम दे, तब बिहार खुशहाल हो सकता है। वरना बिहार में दूसरी परिस्थिति पैदा हो सकती है, जिसकी जिम्मेदारी केन्द्र की होगी। मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूं।

मै यही निवेदन करना चाहता हूं और उपाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। केन्द्र की सबसे लम्बी सूची (सी) कैटेगरी की है और उसमें बिहार को रखा गया है। दूसरी जो कैटेगरीज हैं उनकी दिनरात बढ़ोत्तरी हो रही है लेकिन कैटेगरी (सी) की नहीं हो रही है। बिहार में एनएच-57 भी है, एक्सप्रेस हाइवे भी है जो सिल्चर से पोरबंदर तक है। उसमें मुजफ्फरपुर से फारबिसगंज तक कोई प्रगति नहीं हो रही है। पैसा अलॉट होता है और वहां पर कहते हैं कि एस्टीमेट नहीं आता है। जब एस्टीमेट भेज दिया जाता है तब वह फाइनेंस डिपार्टमेंट को चला जाता है। फाइनेंस का कोई मैम्बर है वह कहता है कि बाढ़ क्या होती है, फ्लड-प्रोन एरिया क्या होता हैâ€¦(व्यवधान)उसका पैरामीटर क्या होता है?मेरा अनुरोध है कि (सी) कैटेगरी को बदलकर उसमें पैसा रिलीज किया जाए और वहां एनएच की स्थिति को सुदृढ़ किया जाए। केवल मूर्ति लगाने से कुछ होने वाला नहीं है। विकास के काम करने के लिए संकल्प चाहिए, इच्छा-शक्ति चाहिए। इस सरकार में इच्छा-शक्ति की कमी है। सभी जानते हैं कि बिहार क्रांतिकारियों की धरती है। बिहार जब गर्म होता है तो पूरे देश की दिशा बदल देता है। इसलिए कहता हूं कि बिहार अगर गर्म हो जाएगा तो आप लोग बेचैन हो जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि बिहार पर इससे ज्यादा प्रहार मत कीजिए, बिहार के साथ सौतेला व्यवहार मत कीजिए और उसे मुख्य-धारा से जोड़िये। उसे मुख्यधारा में जुड़ने का अवसर दीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय : कॉलिंग-अटेंशन में रूल 197 के मुताबिक जो लिस्ट है उसमें पांच से ज्यादा बोलने वाले नहीं हैं। चार का सवाल-जवाब भी हो गया है। माननीय अध्यक्ष जी ने तीन-चार सदस्यों को एक-एक सवाल पूछने की स्पेशन पर्मिशन दी है। इसलिए एक-एक सवाल पूछियेगा। उसके बाद मिनिस्टर साहब जवाब देंगे। श्री राम विलास पासवान जी।

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : अभी हमारे माननीय सदस्य रघुवंश जी, देवेन्द्र जी और झा साहब ने मुद्दे उठाए। बिहार में तो समस्याएं ही समस्याएं है, लेकिन फिर भी मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं कि देश का एक राज्य तो बहुत विकसित हो जाए और एक पिछड़ा हुआ रह जाए तो क्या देश की एकता और अखंडता पर भविय में खतरा उत्पन्न नहीं हो जाएगा। हम सभी भारत मां की संतान हैं। अगर एक बच्चे के एक अंग को लकवा मार जाए और दूसरा अंग बहुत मजबूत होता जाए तो देश का क्या होगा। इसलिए बिहार की चिंता केवल बिहार के लोगों को ही नहीं होनी चाहिए बल्कि पूरे देश के लोगों को होनी चाहिए। इसलिए यह जो जवाब आया है यह असंतोाजनक जवाह है। जिस समय बिहार का बंटवारा हुआ था, उस समय बिहार के लोगों के मन में कितनी आशाएं जगी थीं कि सब कुछ झारखंड में चला गया है तो हमें यह मिलेगा, हमें वह मिलेगा। माननीय मंत्री जी ने जिस भााा का प्रयोग किया है हम उस भााा को समझ नहीं पाये हैं। ऐसा लगता है कि "खोदा पहाड़ निकली चुहिया" वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। हम यहां रोड, बिजली, पन-बिजली, सिंचाई पर डिस्कशन कर रहे हैं। यह सब क्या हो रहा है? जो चीज हमारे यहां पहले थीं जैसे बरौनी थर्मल कारखान था, उसको सरकार ने बंद कर दिया, सिंदरी का कारखाना सरकार ने बंद कर दिया। एचईसी रांची बंद हो गया। अमजोर का कारखाना बंद हो गया। वहां कोई नयी परियोजना शुरू नहीं हो रही है। चीनी मिल से लेकर सभी कारखाने एक के बाद एक बंद हो रहे हैं। सहकारी संस्थाओं का पैसा रोक दिया गया है। अशोक पेपर मिल से लेकर तमाम चीजें बंद हो रही हैं। ठीक है, दक्षिण के राज्य खुश हो लें।

बहुत तरक्की कर रहे हैं। वहां नई-नई टैक्नोलोजी आ रही है, लेकिन बिहार जैसा राज्य पिछड़ा है। सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मैं पूछना चाहता हूं, क्या आप बिहार को देश से अलग करना चाहते हैं? कुछ दिनों के बाद सभी राज्य कहेंगे कि हमारा पैसा बिहार में क्यों जाएगा, सारा कुछ तो हम कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में क्यों जाएगा, सारा कुछ तो हम कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अपने ही देश में दो तरह के राज्य होंगे - एक विकसित राज्य और दूसरा अविकसित राज्य। जो अविकसित राज्य हैं, उनको इस तरीके से ट्रीट किया जाएगा कि वहां उग्रवाद फैले, गन्दा नाला बहे और दूसरी तरफ स्वर्ग को भोगो। इसलिए मैं समझता हूं कि यह गम्भीर मामला है और मैं नहीं समझता हूं कि मंत्री जी इन समस्याओं का जवाब देने में सक्षम हैं। उनको तो जो नोट मंत्रालय से मिला होगा, वही वे पढ़ देंगे। इस विाय में यदि गम्भीरता से बात करनी है, तो प्रधान मंत्री जी योजना आयोग के अध्यक्ष हैं और अन्य सभी संबंधित मंत्रालयों को इस विाय पर बात करने के लिए बुलाना चाहिए। जिस प्रकार नॉर्थ-ईस्ट के विकास के लिए बैठक करते हैं, वहा जाते हैं, तो सभी डिपार्टमेंट्स को लेकर वहां जाते हैं, हर मंत्रालय को लेकर वहां जाते हैं, उसी तरीके से प्रधान मंत्री

को हर मंत्रालय के लोगों को बुलाना चाहिए, पोलिटकल लोगों को बुलाना चाहें, तो बुला सकते हैं और नहीं बुलाना चाहें, तो न बुलायें, लेकिन पीस वर्स से काम नहीं चलेगा। अगर बिहार को बढ़िया तरीके से पैकेज देना है, तो दीजिए और उसकी मोनिटरिगं कीजिए। हम जानते हैं कि इसमें आरोप-प्रत्यारोप लगेगा। केन्द्र सरकार कहेगी कि राज्य सरकार द्वारा क्या होता है और एनएच के बारे में कहेंगे कि वहां कोई टैंडर नहीं निकाला जाता है। इन बातों में कोई गम्भीरता नहीं है, यदि इस समस्या पर गम्भीरता पूर्वक विचार करेंगे, तो बिहार का विकास होगा, अन्यथा बिहार अपने रास्ते पर जा ही रहा है। बिहार का भविय क्या होने वाला है, कुछ कहा नहीं जा सकता है। हम लोग बिहार प्रदेश के निवासी हैं, हम जान रहे हैं कि आगे आने वाले 20-25 वर्षों में बिहार की क्या स्थिति होगी, जब यह सोचते हैं तो रुह कांप जाती है। यदि बिहार को देश का अंग बनाकर रखना है, भारत का अंग बनाकर रखना है, तो बिहार के विकास के लिए एक स्पेशल पैकेज दीजिए। सामान्य रूप में एक-एक रुपया देने से काम नहीं चलने वाला है। आपको बिहार के लिए स्पेशल पैकेज बनाना होगा और उस पैकेज के कार्यान्यवन को भी देखना होगा। इसके लिए स्वयं प्रधान मंत्री जी को इन्टरैस्ट लेना होगा, तब जाकर बिहार बचेगा। नहीं तो चर्चा करने के लिए हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन भविय में बिहार में क्या होगा, इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है।

इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे दो मिनट बोलने के लिए समय दिया।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश के अनुसार सिर्फ मंत्री जी से सवाल पूछना चाहता हूं।

महोदय, जब बिहार राज्य के बंटवारे का सवाल आया, तो हम उसके विरोध में खडे थे। हमारे साथ देवेन्द्र प्रसादजी भी थे। दूसरे, नीतीश कुमार जी को भी जानकारी है, उपप्रधान मंत्री जी से बात की थी, तो कहा गया था कि राज्य की जो भी क्षति होगी, उसकी भरपाई करेंगे। महोदय, योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। हम आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था, उस कमेटी ने अब तक क्या समीक्षा की है? क्या योजना आयोग ने इस बात की भी समीक्षा की कि राज्य के बंटवारे से राज्य को प्रतिर्वा कितना नुकसान उठाना पड़ता है? इसी के साथ मैं यह भी जानना चाहता हूं, अगर उन्होंने समीक्षा की, तो राज्य के विकास के लिए कौन-कौन सी योजनायें और धनराशि बिहार को आवंटित की है? मंत्रालय द्वारा 100 पिछड़े जिलों का चयन किया गया है, उन पिछड़े जिलों में बिहार का नाम नहीं है, इसलिए कि बिहार पिछड़ा हुआ नहीं है। दूसरी तरफ उग्र वादी जिलों के चयन में बिहार के 8 जिलों का चयन किया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि क्या विकास के लिए हर जिले को उग्रवाद का रूप पकड़ना आवश्यक है? साथ ही मैं यह भी बताना चाहता हूं कि बिहार में 34 जिले हैं। इन 34 जिलों में से उत्तर बिहार में लगभग 19 जिले हैं।

इन्होंने 19 जिलों में एक भी जिले का चयन नहीं किया है। योजना आयोग के उपाध्यक्ष के माध्यम से क्षति-पूर्ति की चर्चा हुई थी। उत्तर बिहार के छपरा, सीवान, गोपालगंज और अन्य जो जिले हैं क्या वह उन्हें शामिल करना चाहते हैं जिससे वहां भी विकास की गति तेज हो।

एनएच के संबंध में इन्होंने कहा कि राज्य को पैसा देते हैं, लेकिन राज्य सरकार पैसा खर्च नहीं करती। यह रुपया देते हैं या नहीं, हम मानते हैं कि यह सरासर गलत बयान देते हैं। हम जानना चाहते हैं कि यदि यह रुपया देते हैं और राज्य सरकार खर्च नहीं करती है तो वैसी परिस्थिति में एनएचआई के माध्यम से, जिन पथों को एनएच बना दिया है, जो इनकी एजेंसी है, उसके माध्यम से जिन सड़कों को एनएच में लिया है, यह उनका काम कराना चाहते हैं या नहीं? पटना हाई कोर्ट का भी यह निर्णय आया था कि केन्द्र सरकार चाहे तो दूसरी एजेंसी से काम करा सकती है। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के संबंध में मैंने सवाल उठाया था कि क्या राइट्स से काम कराया जाएगा? राज्य सरकार पहले इसके लिए तैयार नहीं हो रही थी। बाद में तैयार हो गई। अब राइट्स कह रहा है कि हम बिहार में काम नहीं करेंगे। **जब राइट्स ने इं**कार कर दिया तो कौन सी एजेंसी का चयन किया है जिससे प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना का काम बिहार में हो सके। रेल विभाग की रेल विस्तार की योजना दो साल से योजना आयोग में पैडिंग पड़ी है। मसला महाराजगंज रेल लाइन विस्तार का था। क्या आप इस योजना को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत करा कर तुरन्त यह काम करवाना चाहते हैं?

उपाध्यक्ष महोदयः क्या रेलवे का मामला भी पैकेज में आना चाहिए?

श्री प्रभुनाथ सिंह : वह योजना आयोग में पैडिंग है। योजना आयोग ने अब तक समीक्षा करके कोई नई योजना नहीं दी और यह नहीं बताया कि कितना घाटा, मुनाफा बिहार को हुआ? यदि उसका हिसाब नहीं किया तो हम जानना चाहेंगे कि क्या राजनीति से रिटायर्ड जो लोग हैं या जो सरकार के विश्वासपात्र अफसर चाटुकार होते हैं, जो योजना आयोग में अभी हैं और वहां उपनिवेश बनाए हैं, क्या योजना आयोग को भंग करने का सरकार विचार रखती है ताकि उपनिवेश न बन सके।

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस समय बिहार पैकेज देने की बात हुई थी सभी सांसदों ने मिल कर संयुक्त रूप से एक मैमोरंडम दिया था। उसमें बिहार के विकास से संबंधित बातों को कहा था। बिहार के बंटवारे के बाद जो विामता पैदा हो गई थी, उसे दूर करने के लिए और बिहार के लोगों को इस बात की अनुभूति के लिए कि वे देश का वही एक हिस्सा हैं जिन्होंने देश के निर्माण में और देश में आजादी में बहुत बड़ी भूमिका अदा की, हमने कहा था कि भारत सरकार वहां रेल और सिचाई के विकास की तरफ ध्यान दे। वहां के लोगों को बाढ़ और सुखाड़ की स्थिति से निजात दिलाने के लिए, सड़कों की जो बदतर स्थिति है, उसे दूर करने के लिए, सिंचाई की बड़ी-बड़ी योजनाएं जो ठप्प पड़ी हैं, उन्हें चालू करने के लिए, तमाम कल-कारखाने जो बंद होने के कारण रूग्ण हैं जिससे हजारों-हजार नौजवान, कर्मचारी, मजदूर बेकार हैं, उन्हें काम दिलाने के लिए, भूमि सुधार को मजबूरी से लागू करने के लिए कदम उठाए जाएं। वहां लाखों खेत मजदूर भूमिहीन हैं और उन्हें पलायन करना पड़ता है, उनकी स्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाएं। इसके अलावा वहां लाखों बुनकर करघे बंद होने से बेकार हैं। वहां बिजली की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए जाएं। इन तमाम चीजों के लिए पैकेज देने की बात हुई थी। प्रधान मंत्री ने स्वंय बिहार के सांसदों के साथ बैठक करके इन समस्याओं का निदान निकालने के लिए, उनकी एक-एक समस्या के बारे में जानकारी लेकर सारी स्थिति को स्पट करने के लिए कहा था।

ताकि बिहार उग्रवाद के रास्ते पर न बढ़े। बिहार किसी भी तरह से इस स्थिति में न जाये जो पूरे देश के लिये चिन्ता का कारण बनऔर सरकार की नींद हराम हो। क्या सरकार इसके समाधान के लिये कोई प्रयास करेगी?

उपाध्यक्ष महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र में भारत का प्राचीन विक्रमशिला विश्वविद्यालय है जो पर्यटन की दृटि से बहुत बड़ा स्थान है। उसके सुधार के लिये सरकार क्या करने जा रही है। बिहार की सिंचाई परियोजनाओं में गंगा-बटेश्वर पम्प नहर योजना के निर्माण से 20 हजार एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकती है। इससे न केवल बिहार बल्कि झारखंड के लोगों को भी लाभ पहुंच सकता है। साथ ही स्पट करे कि रेल के विकास के लिये और लूप लाइन बिछाये जाने के लिये सरकार क्या कोई स्पट घोाणा करेगी तथा भागलपुर में एल.पी.जी. गैस प्लाट स्थापना में क्या कर रही है ?

श्रीमती कान्ति सिंह (बिक्रमगंज) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार के बटवारे के बाद वहां की विधानसभा ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करते हुये 1,79,900 करोड़ रुपये के आर्थिक पैकेज की मांग की थी। उस प्रस्ताव का क्या हुआ? लगता है कि केन्द्र सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं है। हमारे बिहार में अमझोर में जो पुराने उद्योग सालों से बंद पड़े हुये हैं, माननीय रेल मंत्री जी ने जाकर देखा था, उनका पुनरुद्धार करने के लिये विशेा पैकेज दिया जाये। जैसा श्री राम विलास पासवान ने बताया कि विभिन्न मंत्रालयों के पदाधिकारियों की बैठक बुलाकर राजस्व में बढ़ोत्तरी के उपाय सुझाये जा सकते हैं। हमारा रोहतास जिला राजा हरिश्चन्द्र के पुत्र रोहित के नाम पर रखा गया था। अगर इस जिले को परियोजना के रुप में लिया जायेगा तो हमारे राजस्व में बढ़ोत्तरी हो सकती है। पहाड़ की गुफा में शिव मन्दिर, जो गुप्तधाम नाम से पर्यटन स्थल है, उसे लिया जा सकता है। इससे राजस्व में बढ़ोत्तरी होगी। उसी तरह से तारा चण्डी मंदिर पहाड़ की गुफा में बसा हुआ है। वह हमारे

क्षेत्र में है।

उपाध्यक्ष महोदय, आरा-सासाराम रेलमार्ग 1996 में स्वीकृत हुआ था लेकिन मात्र 20 किलोमीटर अब तक बन पाया है। यह क्षेत्र धान का कटोरा है। यदि रेलमार्ग बन जाता है तो न केवल लोगों को सुविधा होगी बल्कि राजस्व में भी बढ़ोत्तरी होगी। इससे लोगों को रोजगार भी मिल सकता है।

उपाध्यक्ष महोदय : आप सवाल पूछिये, भााण क्यों कर रही हैं?

श्रीमती कान्ति सिंह : उपाध्यक्ष जी, इसी प्रकार इन्द्रपुरी जलाशय पन-बिजली परियोजना है जिसकी 450 मेगावाट क्षमता है। बिहार सरकार ने जो प्रस्ताव केन्द्र सरकार को भेजा हुआ है, उसे पूरा करवाया जाये। यह काफी समय से केन्द्र सरकार के पास लम्बित है। मैं चाहूंगी कि माननीय मंत्री जी कैमूर पम्प नहर योजना को भी पूरा करवायें। मेरा निवेदन है कि हम भााणबाज़ी न करें। मुझे लोक सभा में आये हुये चार साल हो गये हैं। हर बार बहस होती है लेकिन नतीजा - ' ढाक के वही तीन पात' जहां से चीज चलती है, वहीं आकर रुक जाती है। मेरा मंत्री जी से आग्रह है कि यह कहावत इस बार चरितार्थ न हो, इस पर कार्यवाही होनी चाहिये तभी बिहार का विकास हो सकता है।

15.00 hrs.

डॉ. मदन प्रसाद जायसवाल (बेतिया) : उपाध्यक्ष जी, मेरा सीधा प्रश्न है कि नीतीश जी के अधीन हम लोगों ने एक प्रपोज़ल बनाकर योजना आयोग के अध्यक्ष माननीय प्रधान मंत्री जी को दिया था। उस आवेदन के आलोक में योजना आयोग ने कितनी बार बैठकें की हैं और उस पर योजना आयोग ने क्या फैसला किया है, इसका ब्यौरा हमें चाहिए।

मेरा दूसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैं? हाल ही में इलाहाबाद को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया गया। क्या बिहार में भी पटना विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाएगा?

श्री अरुण कुमार (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरा मध्य बिहार नक्सल प्रभावित क्षेत्र है मगर वहां विकास की भारी संभावनाएं हैं। एग्रीकल्चर में वहां का पुनपुन, दरधा, मोरहर परियोजना है जो बहुत दिनों से लंबित है, क्या सरकार उसको क्रियान्वित कराने का विचार रखती है?

मध्य बिहार में पर्यटक के कई केन्द्र बन सकते हैं जैसे बानावर पहाड़ है जहां अशोक के समय के प्रमाणित अभिलेख हैं। वहां कई ऐसे स्थान हैं जिनसे पर्यटन को बढ़ावा दिया जा सकता है। ये सब राजगीर और नालंदा तथा बोध गया के बगल में हैं। इन सैन्टर्स को भी डैवलप किया जा सकता है। एग्रीकल्चर के लिये वह बून है। पुनपुन, दरधा, मोरहर परियोजना पर भारत सरकार को एक पैकेज के तहत क्रियान्वयन कराने के बारे में कई बार चर्चा हो चुकी है। उस बारे में भी बताएँ कि कब तक वह पूरी होगी?

श्री निखिल कुमार चौधरी (कटिहार) : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की बदहाली पर पूरी चर्चा हुई है। महोदय, बिहार बँट गया -- जो रह गया वह खेती प्रधान क्षेत्र रह गया। मेरा सीधा प्रश्न है कि खेती पर आधारित उद्योग लगाने के लिए क्या केन्द्र सरकार की कोई बृहत्तर योजना है? अगर है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे क्षेत्र कटिहार और उसके अगल-बगल के जो जिले हैं, जहां पटसन उत्पादन होता है, वहां आर.बी.एच.एम. जूट मिल है, जो बीमार है और जहां हज़ारों मज़दूर काम करते हैं, उस जूट मिल के रिवाइवल के लिए क्या कोई योजना सरकार रखती है? तीसरा सवाल यह है कि â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कालिंग अटैन्शन में एक ही सवाल पूछा जा सकता है।

श्री निखिल कुमार चौधरी : यहां माननीय सदस्यों ने पांच-छः सवालों का भााण कर दिया।

उपाध्यक्ष महोदय : उन्होंने नोटिस दिया है।

श्री निखिल कुमार चौधरी : महोदय, बिहार में जो सड़कों की दुर्दशा है, वहां राज्य सरकार ने भारत सरकार को बदनाम करने के लिए बोर्ड लगा दिये हैं कि यह सड़क भारत सरकार के अधीन है। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि जहां बदनाम करने की कोशिश की गई है, उस बदनामी से बचने के लिए एन.एच. के सुधार की दिशा में आपके द्वारा कौन से तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं? चौथा सवाल यह है कि बिजली की स्थिति सुधारने के लिए बिहार में कौन से तात्कालिक उपाय किये जा रहे हैं?

उपाध्यक्ष महोदय : बिहार पर पाँच-छः सवाल एक ही सवाल हो जाते हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : मंत्री जी सवालों का उत्तर दें, लिखा हुआ मत पढें। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मंत्री जी को जवाब देने का मौका तो दें। आपको संतुटि न हो तो फिर पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

DR. V. SAROJA (RASIPURAM): Sir, I also want to make a submission which is not only for the benefit of Bihar but also for the benefit of other States.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Saroja, this is Calling Attention.

DR. V. SAROJA : Sir, I seek your permission to place on the Table a copy of the Supreme Court judgement which may jeopardise all the discussion that we are having. I would also like to know whether the Government of India has already taken note of the points which are mentioned in the Supreme Court direction.

श्री प्रभुनाथ सिंह : इससे बिहार का क्या संबंध है? â€¦ (व्यवधान)

DR. V. SAROJA : This is for the benefit of everybody. Bihar is an under-developed State and we are all concerned about it.

The recent Supreme Court judgement says:

> "In continuation of this Ministry's letter of even number dated 10.7.2003, please find enclosed herewith the copy of the order.
>
> In compliance with the orders of the Supreme Court, the undersigned is directed to convey the Net Present Value for the forest area approved for diversion after 30.10.2002 for non-forestry purpose shall be collected at the rates prescribed by the Supreme Court in their order dated 30.10.2002 issued on 12.11.2002."

Sir, I would like to know whether the Government has taken note of it as this is going to jeopardise the discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Dr. Saroja, this is a Calling Attention Motion specifically for a financial package to Bihar for its development purpose. Therefore, whatever may be the judgement, that will be taken care of by the Government. The Minister is specifically directed to answer the questions already asked by the hon. Members.

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PLANNING, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF STATISTICS AND PROGRAMME IMPLEMENTATION, MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY AND MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENTS OF ATOMIC ENERGY AND SPACE (SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE): Sir, I appreciate the concern expressed by the hon. Members about the State of Bihar. If I were to be asked about my own State, probably, I would have also expressed a similar concern.

This is a Calling Attention Motion where I have made a statement and the hon. Members are entitled to ask only clarificatory questions on that statement. I am sorry to say that that has not been done. In fact, a debate has taken place. But, to the best of my ability, I will try to answer the questions asked.

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हमने सवाल ही पूछा है। â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय कह रहे हैं कि मैंने जवाब दिया है और उसके मातहत ही सवाल पूछे जाने चाहिए। सवाल फायनेंश्यल पैकेज का है और इन्होंने फायनेंश्यल पैकेज के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है, क्या यह हमारी गलती है ?

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जो सवाल पूछा है, उसका उत्तर नहीं दिया है। हमने एक-एक सवाल अलग-अलग पूछा है और मंत्री महोदय ने एक भी स वाल का उत्तर नहीं दिया है बल्कि ये पहले से ही ऐसी भूमिका बांध रहे हैं जिससे लगता है कि ये सब गड़बड़ करने वाले हैं। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा सुनने के बाद पुनः क्लैरिफिकेशन पूछना चाहेंगे, तो मैं आपको प्रश्न पूछने के लिए पुनः समय दूंगा।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, अगर मंत्री जी जवाब देने में सक्षम नहीं हैं, तो प्रधान मंत्री जी को जवाब देना चाहिए। â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, हाउस में प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और उप प्रधान मंत्री जी ने आश्वासन दिया था और अब मंत्री महोदय यहां लिखी हुई किताब पढ़ेंगे, तो कैसे काम चलेगा ? â€¦ (व्यवधान)

श्री सुबोध राय (भागलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री यहां उपस्थित हों और वे जवाब दें। â€¦ (व्यवधान)

SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: Sir, I seek your protection.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I would read out one sentence from the Minister's statement for the benefit of the Members. Let me tell you that if you go through the statement, you will find many things. Under the Special Plan for Bihar, it is said:

> "The Central Government has already approved a proposal for investment of Rs. 1000 crore in identified projects to be implemented in the State of Bihar."

श्री रघुनाथ झा : यह तीन र्वा में एप्रूव हुआ है और केवल 77 करोड़ रुपए गए हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : मुझे मालूम नहीं है, इसमें लिखा है।

श्री रघुनाथ झा : उपाध्यक्ष महोदय, आपको मालूम नहीं है, लेकिन हमें मालूम है, इस 77 करोड़ रुपए से इस ध्यानार्काण प्रस्ताव का कोई मतलब नहीं है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, यह हर राज्य को मिलता है। बिहार को अलग से जो आर्थिक पैकेज देना था, उस बारे में बताएं। जो आप पढ़ रहे हैं, यह विशे पैकेज का मामला नहीं है। यहां विशे पैकेज की चर्चा हुई है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, ये तो 77 करोड़ रुपए मात्र हैं। यह तो रूटीन का मामला है। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले आप मंत्री जी का जवाब सुन लें। यदि आप सैटिस्फाइड नहीं होंगे, तो मैं आपको पुनः सवाल करने का मौका दूंगा।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे महत्वपूर्ण सवाल पर प्रधान मंत्री और उप प्रधान मंत्री को जवाब देना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय के जवाब देने का कोई मतलब नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जवाब दें।â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, बिहार की फटेहाली को गम्भीरता से नहीं लिया जा रहा है। â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मुखर्जी साहब, हम लोगों के अच्छे मित्र हैं।

इनके प्रति हम लोगों का बहुत रिगार्ड है, लेकिन मुद्दा ऐसा है कि ये पूरे स्टेट का मामला है, कोई पार्टी का नहीं है।â€¦ (व्यवधान)इसलिए सब एक साथ हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि इसमें आउट ऑफ द वे जाकर,â€¦ (व्यवधान)इस मामले में हम सब एक हैं, यह पैकेज का सवाल है। आपने एक हजार करोड़ रुपया पढ़ कर सुनाया और दिया गया केवल 77 करोड़ रुपया। मंत्री जी, इसका क्या जवाब देंगे। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा,â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, इनसे पूछा जाए कि एक हजार करोड़ रुपया कब गया?â€¦ (व्यवधान)यह तो आंख में धूल झोंकने का काम है।â€¦ (व्यवधान)मंत्री जी पूरी जवाबदेही स्वीकार करें,ये सदन को बताएं कि कितना रुपया गया है?â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री जी इसका जवाब दें।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप मेरी बात सुनने की कृपा करें। मैंने कहा कि यह कालिंग अटेंशन है, आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए।

â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: This Calling Attention is meant to call the attention of the Minister of State in the Ministry of Planning to the need for a financial package to Bihar for development works in the State.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let me complete. उसके बाद कुछ होगा तो मैं भी आपको बताऊंगा। आप पहले पूरी बात सुन लीजिए।

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Accordingly, the hon. Minister made a statement. That statement is before you.

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने एक वाक्य पढ़ कर सुनाया, कब हुआ, क्या हुआ और क्या नहीं हुआ, यह आपको मेरे से ज्यादा पता होगा, क्योंकि आप बिहार से आते हैं और मेरे से ज्यादा आपको मालूम है।

â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : आप क्या समझते हैं कि हम लोगों ने जो प्रश्न पूछा था, वह इर्रिलेवेंट है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : बिलकुल नहीं।

SHRI RAM VILAS PASWAN : Cabinet Minister for this subject is the hon. Prime Minister. ...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : आप पहले मेरी पूरी बात सुन लीजिए। मैंने कहा कि आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए। इन्होंने दो वाक्य बोले और उसके बाद आपने इन्हें बोलने नहीं दिया। इसलिए मैंने कहा कि आप पहले मंत्री जी की पूरी बात सुन लीजिए।

â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, ऐसे सवाल पर प्रधानमंत्री जी आकर जवाब दें।â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : महोदय, विाय की गंभीरता को देखें। प्रधानमंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिएâ€¦ (व्यवधान)हिन्दुस्तान में पूरे देश की जनसंख्या के हिसाब से भी बिहार दूसरे नम्बर पर है और यह सबसे गरीब है। केन्द्र सरकार विाय की गंभीरता को क्यों नहीं समझती है?â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : महोदय, जिस पैकेज के लिए माननीय नीतीश कुमार जी, उस समय के सारे मंत्रिमंडल के लोग तथा सांसदों ने प्रधानमंत्री जी को कहा, उसकी उन्होंने बैठक की और उसे रिव्यू किया कि कितना गया।â€¦ (व्यवधान)आप ये बताएं कि मीटिंग की या नहीं?â€¦ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : महोदय, बिहार पर तीन घंटे की पूरी चर्चा कराइए।â€¦ (व्यवधान)प्रधानमंत्री जी, इसका जवाब दें, कालिंग अटेंशन से बिहार की चर्चा खत्म नहीं होगी।â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, इसमें मुख्य मुद्दा यह है कि उप प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, जिस दिन राज्य के बंटवारे का यहां बिल पास हो रहा था, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ। इनके यहां कोई फाइल नहीं जाती है। यह क्या इसका उत्तर दे पाएंगे।â€¦ (व्यवधान)इसलिए प्रधानमंत्री जी सदन में आएं और इसका उत्तर दें तथा हमें संतुट करें कि बिहार को क्या दे रहे हैं। बंटवारे के बाद बिहार की स्थिति दिन-प्रति-दिन बिगड़ती जा रही है। ऐसी स्थिति में जब तक प्रधानमंत्री जी इसका जवाब नहीं देंगे तब तक सदन संतुट नहीं होगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोग इन्हें इसलिए कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें संतुट नहीं कर पाएंगे। इनके प्रति हम लोगों की सहानुभूति है

और उस सहानुभूति को व्यक्त करते हुए हम लोग चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी आकर जवाब दें। यह मंत्री जी के बलबूते के बाहर की चीज है। यह पॉलिसी मैटर है और केबिनेट मिनिस्टर ही पॉलिसी मैटर को डील करते हैं। â€¦ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हमने इनको तो पहले भी सुन लिया। लेकिन बिहार बंटवारे के बाद क्या हुआ?â€¦ (व्यवधान)

युवक कार्यक्रम और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल) : आप इनको सुन लें, अगर आपकी तसल्ली न हो तो वह बाद की बात है। आप इनको सुनिये। आप एक मंत्री को बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। â€¦ (व्यवधान)

कुंवर अखिलेश सिंह : विजय गोयल जी, आप लोगों से हम लोगों को सहानुभूति है, इन मंत्री जी से भी हमें सहानुभूति है। ये **बेचारे** किसी लायक नहीं हैं।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: I will give the answer. Please listen to me....(*Interruptions*) You must have the patience to listen to me....(*Interruptions*)

श्री विजय गोयल : आप पहले इनकी बात सुन लीजिए, उसके बाद बोल लीजिए, जो कुछ बोलना है।

श्री प्रभुनाथ सिंह : इन्होंने तो पढ़कर सवालों का उत्तर दिया है।â€¦ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : मंत्री जी गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। आप फाइनेंशियल पैकेज पर कुछ बताइये।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: Let me answer the question. Please give me a chance to answer the question. May I proceed?...(*Interruptions*)

श्री प्रभुनाथ सिंह : जब ये बोल लेंगे तो जवाब ही नहीं मिलेगा। उप-प्रधानमंत्री जी का या प्रधानमंत्री जी उत्तर दें, चेयर से यह निर्देश हो।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: The Calling Attention is addressed to the Minister of State in the Ministry of Planning. मैं सभी लोगों से अपील करूंगा कि कालिंग अटेंशन मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग को एड्रैस किया गया है। अगर आप उत्तर सुनने के बाद सैटिसफाई नहीं हों तो आगे क्या करना है, वह तय करेंगे।

â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : यह मिनिस्ट्री प्रधानमंत्री जी के जिम्मे है। â€¦ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : यह बिहार के 8.5 करोड़ लोगों का सवाल है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: May I proceed to answer the question?...(*Interruptions*) May I answer the question which has been raised here?...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, आप सुनिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप आसन से निर्देश दीजिए, प्रधानमंत्री जी यहां आकर हम लोगों के सवालों का उत्तर दें। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आसन से ऐसा कोई निर्देशन गवर्नमेंट को नहीं दे सकता।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप इस आसन पर मौजूद थे, जब दो दिन तक यहां बिहार बंटवारे का बिल पास नहीं हो सका। जब उप-प्रधानमंत्री जी ने आश्वासन दिया, इसके बाद यहां लोक सभा में बिल पास हुआ था। उस आश्वासन के बाद सरकार मुकर गई है। उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस पर हम कैसे समझौता कर सकते हैं, इसलिए यहां पर प्रधानमंत्री जी को आना चाहिए। अब इस पर कोई बात नहीं होगी।â€¦ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : इस पर कोई समझौता नहीं होगा।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, आप चेयर पर हैं, आप सदस्यों की भावनाओं को क्यों नहीं महसूस कर रहे हैं? बिहार के सदस्यों की भावना है, मंत्री जी के प्रति हम लोगों का पूरा रिगार्ड है, लेकिन जिस तरह का जवाब आया है, इस जवाब के चलते इससे हम लोगों की समस्या का निदान नहीं होने वाला है। समस्या का निदान तब होगा, जब इसके केबिनेट मिनिस्टर, जो प्रधानमंत्री हैं, जो योजना आयोग के चैयरमैन भी हैं, वे यहां रहें, जवाब दें, तब उनसे सवाल-जवाब भी किया जा सकता है और वे समस्या का निदान भी कर सकते हैं। इन्होंने तो जो जवाब दिये हैं, इसी को जस्टीफाई करते रहेंगे, उससे क्या मतलब है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: Shri Paswan, I will not try to justify the statement. I will try to answer his question put to me. Please give me a chance to answer the question....(*Interruptions*)

कुंवर अखिलेश सिंह : विजय गोयल जी, यह चांदनी चौक नहीं है, बिहार बहुत सी समस्याओं से ग्रस्त है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: I am going to answer that question....(*Interruptions*)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : जब बिल पास हो रहा था तो इसी सदन में प्रभुनाथसिंह जी ने और हम लोगों ने बायकाट किया था, तब कहा गया था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक सैल गठित किया गया है। यह बिल में है कि फाइनेंशियल मैमोरेण्डम के साथ ही बिल पास होगा, यह नियमों में बाकायदा हम लोगों ने उठाया, प्रोसीडिंग्स को देख लिया जाये। बिहार के सवाल को हमने और प्रभुनाथ सिंह जी ने उठाया और सभी माननीय सदस्यों ने साथ दिया था, सभी ने उठाया। मेरा व्यवस्था का सवाल इसीलिए है, जब बिल में ही फाइनेंशियल मैमोरेण्डम के साथ ही किसी राज्य का बंटवारा हो सकता है।â€¦ (व्यवधान)

SHRI SATYA BRATA MOOKHERJEE: Let me answer that question.â€¦ (*Interruptions*)

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : प्रधान मंत्री जी को उत्तर देना होगा। â€¦ (व्यवधान)

भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोा कुमार गंगवार) : मैं पहले भी कह रहा था। â€¦ (व्यवधान)मैं तो शुरू में ही कह रहा था। â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी से हमने अवगत कराया था। â€¦ (व्यवधान)जब बिहार पर बहस हुई तब उन्होंने हमसे पूछा था कि किसने इसका उत्तर दिया था। â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, उसे प्रोसीडिंग्स में से निकाल कर देखा जाये। â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, जिस दिन बिहार राज्य का बंटवारा हुआ, उस दिन की प्रोसीडिंग्स देखी जाये। उस दिन हमने यह सवाल किया था। â€¦ (व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप 9 अगस्त, 2002 की प्रोसीडिंग्स निकाल कर देखिये। â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, आप 2 अगस्त, 2002 की प्रोसीडिंग्स को निकाल कर देख लीजिए। â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Devendra Prasad Yadav, I am on my legs. Will you please resume your seat now?

...(*Interruptions*)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं खड़ा हूं। आप कम से कम मुझे सुनने की कृपा कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : हम आपको नहीं सुनेंगे तो किसे सुनेंगे। â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : हम आपको जरूर सुनेंगे। â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मिनिस्टर साहब ने कहा है कि वे इसी जवाब पर नहीं रहेंगे। आप इसके आगे जो सवाल पूछेंगे, उसका वह जवाब देंगे। आप पूरा जवाब सुनने के बाद कहिये। वह आपसे अपील कर रहे हैं। वह तो स्टेटमैंट है। इसके अलावा आपने जो सवाल पूछा है, वह उसका जवाब देने के लिए तैयार हैं। वह तैयार होकर जवाब देते हैं और उनका जवाब सुनने के बाद भी आप संतुट न हों तब भी आप सवाल पूछ सकते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है।

...(व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : पहले भी यह सवाल उठा था। â€¦ (व्यवधान)रघुवंश बाबू ने इसे उठाया था। उस समय श्रीमती वसुंधरा राजे योजना विभाग की प्रभारी थीं। उन्होंने उस समय जवाब दिया था। जब प्रधानमंत्री जी ने पूछा कि किसने जवाब दिया तो हमने बताया कि उन्होंने जवाब दिया है। उसी समय उन्होंने कहा कि नहीं, वित्त मंत्री जी को इसका जवाब देना चाहिए था। हमें जवाब देना चाहिए था। यह क्या जवाब देंगे ? â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, प्रधान मंत्री जी ने भी इच्छा व्यक्त की थी कि स्टेट मिनिस्टर इसका जवाब नहीं दे पायेंगे। एक बार जब बिहार पर बहस हुई, तब प्रधान मंत्री जी ने â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप लोग मेरे लिए आपत्ति मत खड़ी करिये।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमारा एक निवेदन है कि आप एक तिथि दे दीजिए और उस दिन प्रधान मंत्री जी जवाब दे दें। â€¦ (व्यवधान)दूसरी कार्यवाही शुरू हो। इसमें विवाद न हो। â€¦ (व्यवधान)आप हमारी सुविधा के अनुसार डेट न देकर प्रधान मंत्री जी की सुविधानुसार डेट दे दीजिए। â€¦ (व्यवधान)हम नहीं कहते कि वे कल बयान दें। â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष महोदय, हम लोगों ने तीन साल तक बर्दाश्त किया है। हम तीन दिन और बर्दाश्त कर लेंगे। â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, आप कालिंग अटैंशन के जवाब को स्थगित करें और प्रधान मंत्री जी को जवाब देने के लिए कहें। â€¦ (व्यवधान)यहां श्री विजय गोयल जी बैठे हुए हैं। विजय गोयल जी, यह बिहार है, चांदनी चौक नहीं है। बिहार की समस्या अलग है और चांदनी चौक की समस्या अलग है। इसलिए आप उस समस्या को गंभीरता पूर्वक समझिये। â€¦ (व्यवधान)

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नागमणि) : आप बिहार में किडनैपिंग को बंद कराइये।â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : यह कौन बोल रहा है ? â€¦ (व्यवधान)

15.23 hrs.

(At this stage, Dr. Raghuvansh Prasad Singh came and stood on

the floor near the Table)

15.23-1/4 hrs.

(At this stage, Dr. Prabhunath Singh and some other hon"ble

Members came and stood on the floor near the Table)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Nothing will go on record.

(Interruptions) â€¦*

*** Not Recorded**

15.24 hrs.

(At this stage, Dr. Raghuvansh Prasad Singh, Shri Prabhunath Singh and some other hon"ble Members went back to their seats)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Mr. Parliamentary Affairs Minister, please control your Minister.

...(*Interruptions*)

श्री अरुण कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, यह बहुत गंभीर सवाल है। तीन वर्षों तक बिहार के इस सवाल पर सरकार लुका-छिपी करती रही है।â€¦ (व्यवधान)इसलिए इस विषय पर प्रधान मंत्री जी का जवाब ही मान्य है। इस विषय पर दलों का सवाल नहीं है, पूरे बिहार के अस्तित्व का सवाल है। â€¦ (व्यवधान)इसलिए कटिंग ऐक्रास दी पार्टी लाइन सब लोगों ने यही सवाल उठाया है। आज बिहार के अस्तित्व का सवाल है।â€¦ (व्यवधान)अभी तक जिन राज्यों को पैकेज दिया गया है, माननीय प्रधान मंत्री जी द्वारा दिया गया है।â€¦ (व्यवधान)इसलिए बिहार की जनता इसमें निश्चित रूप से प्रधान मंत्री जी का हस्तक्षेप चाहती है।â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उप-प्रधान मंत्री जी ने हमें आश्वस्त किया था।â€¦ (व्यवधान)

वर्ष 2000 की प्रोसीडिंग्स निकाली जाए।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, साढ़े तीन बजने वाले हैं। साढ़े तीन बजे से प्राईवेट मैम्बर्स बिजनेस शुरू हो जाएगा।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी शुरू नहीं हुआ है।

श्री राम विलास पासवान : वैसे भी अब मंत्री जी जवाब नहीं दे पाएंगे। इसलिए आप इसे स्थगित करके प्राइम मिनिस्टर को डायरैक्ट कीजिए। पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर आ चुकी हैं। सदस्यों की भावना को समझिए।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: I am on my legs.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी ने स्वयं कहा था कि यह स्टेट मिनिस्टर - प्लानिंग का विाय नहीं है।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर पहुंच गई हैं। एक मिनट इनकी बात सुनने के बाद हम फैसला करेंगे।

...(व्यवधान)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुामा स्वराज) : यहां इस समय जो प्रश्न उठाया गया है, वह यह है कि बिहार की गंभीर अर्थव्यवस्था के मामले पर प्रधान मंत्री जी का बयान होना चाहिए। इस सदन के कुछ नियम हैं। कॉलिंग अटैंशन मोशन किसी एक स्पैसीफिक मिनिस्टर के नाम एडमिट होता है। उनको लोक सभा सचिवालय से कहा जाता है कि आपके नाम इस विाय को लेकर फलां सांसद ने नोटिस दिया है, आप इसके ऊपर अपना रिप्लाई भेजें। यहां जब मैम्बर खड़े होकर कहते हैं कि "I draw the attention of the Ministerâ€¦" मैं फलां मंत्री का ध्यान आकर्ति करता हूं, तो जिस व्यक्ति के नाम वह नोटिस होता है, वही संबंधित मंत्री खड़े होकर उसका स्टेटमैंट देता है। उसकी स्टेटमैंट के ऊपर चर्चा होती है। उस चर्चा का जवाब वह मंत्री देता है।â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Let her finish.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seats.

...(*Interruptions*)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Shri Pappu Yadav, let her complete.

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : मैं आपकी बात सुनूंगा। आप ऐसा क्यों करते हैं।

...(व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यह स्टेट मिनिस्टर, प्लानिंग के जूरिस्डिक्शन में नहीं है। â€¦ (व्यवधान)इसका जवाब वित्त मंत्री जी अथवा प्र धान मंत्री जी दें।â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुामा स्वराज : मैं उसी का जवाब दे रही हूं।â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : पार्लियामैंट्री अफेयर्स मिनिस्टर को जानना चाहिए कि कोई भी मैम्बर कभी भी राज्य मंत्री के नाम से नहीं लिखता। वह जब भी लिखता है, मंत्री लिखता है।â€¦ (व्यवधान)

सुामा जी, आप नहीं थीं। कॉलिंग अटैंशन का फार्म निकाल कर देखिए। उसमें राज्य मंत्री नहीं लिखा हुआ है, उसमें संबंधित मंत्री लिखा हुआ है। संबंधित मंत्री का मतलब होता है कैबिनेट मंत्री, संबंधित मंत्री का मतलब राज्य मंत्री नहीं होता। आप क्यों ऐसा कर रही हैं।â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुामा स्वराज : àाननीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने मिनिस्टर ऑफ प्लानिंग को नोटिस नहीं दिया है, यह सच है। जो प्रभुनाथ सिंह जी और रघुवंश प्र ासाद सिंह जी कह रहे हैं कि नोटिस निकाल कर देखें, तो नोटिस निकाल कर देखने की जरूरत नहीं है। आपने इन्हें नोटिस नहीं दिया। मैं ऐसा कब कह रही हूं। आप मेरी बात ही पूरी नहीं होने दे रहे हैं।

लेकिन बहुत बार यह होता है कि किसी और मंत्री के नाम आप नोटिस देते हैं लेकिन स्पीकर साहब अपने विवेक में सही मंत्री जो उन्हें लगता है, उन्हें नोटिस भेजते हैं। मैं यह नहीं कह रही हूं कि आपने इन्हें नोटिस दिया लेकिन यह जब लिस्ट ऑफ बिजनैस में लगा, ऑर्डर पेपर में लगा, जब कार्यसूची में आपके घर पहुंचा तो इनका नाम लगा हुआ था जो इस समय आप ऑब्जेक्शन कर रहे हैं।

मेरा निवेदन यह है कि अगर उस समय स्पीकर साहब से कहा होता कि हमारा नोटिस प्रधान मंत्री के लिए है, आपने नोटिस इनके लिए लगा दिया और जब आपने इनका ध्यानार्काण किया और ये खड़े हुए तो उस समय ये कहते कि हम आपका ध्यानार्काण नहीं कर रहे हैं, हम प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृट करना चाहते हैं। बेशक इसे आज की बजाए कल लगाओ, परसो लगाओ लेकिन प्रधान मंत्री जी का ध्यान आकृट करेंगे, आपको नहीं सुनेंगे।â€¦ (व्यवधान)

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह :उनको हमने सुना लेकिन प्रथम पंक्ति में ही उनकी लाचारी पर हम लोगों ने कहा किâ€¦ (व्यवधान)प्रधान मंत्री जी का ही उत्तर सुनेंगे।â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुामा स्वराज : उन्हीं के स्टेटमेंट पर चर्चा हुई। अब आप उनका रिप्लाई नहीं सुनना चाह रहे हैं।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : पहले कम्पलीट तो होने दीजिए। उसके बाद बोलूंगा।

â€¦ (व्यवधान)

MR. DEPUTY-SPEAKER: Please resume your seats.

...(*Interruptions*)

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है। Sir, I am on a point of order under Rule 197....(*Interruptions*)

श्रीमती सुमा स्वराज : राम विलास पासवान जी, मुझे मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए।â€¦ (व्यवधान)

SHRI RAM VILAS PASWAN : Sir, I want your ruling on my point of order...(*Interruptions*) महोदय, नियम 197 के अन्तर्गत कॉलिंग अटैंशन का जो भी दिया जाता है, वह मंत्री के नाम से दिया जाता है। इस विभाग के मंत्री प्रधान मंत्री जी हैं। प्रधान मंत्री जी ने कहा होगा कि राज्य मंत्री ज वाब देंगे लेकिन नोटिस प्रधान मंत्री के नाम से गया है, यह मैं दावे के साथ कह सकता हूं। इसलिए माननीय मंत्री जी का यह कहना कि स्पेसिफिक मंत्री का सैक्रेटरिएट से चुना होता है, यह लोक सभा सचिवालय का जॉब नहीं है। यह मंत्री के नाम से जाता है और मंत्री कह सकते हैं कि राज्य मंत्री इनका जवाब देंगे। इसलिए संसदीय कार्य मंत्री जो कह रही हैं, वह सही नहीं कह रही हैं। यही मेरा प्वाइंट ऑफ ऑर्डर है।â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुमा स्वराज : प्रभुनाथ जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। आपकी बात का मैं समाधान करूंगी।â€¦ (व्यवधान)राम विलास जी, एक तो आप बिना जानकारी के बात कहते हैं। मेरे हाथ में लोक सभा सचिवालय का कागज है। यह प्रधान मंत्री सैक्रेटरिएट का कागज नहीं है। जो इनको गया है, जहां इनको कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग से होगा। लेकिन मैं यह बात कह रही हूं किâ€¦ (व्यवधान)राम विलास पासवान जी, बीच-बीच में आप खड़े होंगे तो कैसे चलेगा ? मेरा यह कहना है कि इधर से सांसद कह रहे हैं कि हमने इनका जवाब सुन लिया। मैं यह कह रही हूं कि स्टेटमेंट और रिप्लाइ में अंतर है। इन्होंने रिप्लाई नहीं सुना, स्टेटमेंट सुना है। वक्तव्य और जवाब में अंतर है। आपने वक्तव्य सुना है, जवाब नहीं सुना है।â€¦ (व्यवधान)वक्तव्य पर चर्चा हुई है। उन्होंने मंत्री जी का वक्तव्य सुना है। वक्तव्य के ऊपर चर्चा हुई है। अब चर्चा का जवाब होगा। Reply is after the debate and statement is before the debate.

श्री अरुण कुमार : इस पर प्रधान मंत्री जी का जवाब ही उचित होगा।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : प्राइवेट मैम्बर्स का टाइम है। वह मुझे एक्सटेंड करना है, आप बैठिए।

â€¦ (व्यवधान)

श्री रघुनाथ झा : माननीय मंत्री जी ने जो उत्तर दिया है,â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुमा स्वराज : मेरा यह कहना है कि सिर्फ एक मिनट में मैं अपनी बात पूरी करूंगी। मैं आपकी बात का समाधान करूंगी। आपकी बात का समाधान ध ाधान मंत्री जी की बात से होगा न? â€¦ (व्यवधान)मेरी बात ही पूरी नहीं होने देते। अगर बात पूरी नहीं होने देंगे तब कैसे चलेगा ? â€¦ (व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह : आप पर हमें भरोसा है। आप जरूर प्रधान मंत्री जी से बुलवाइएगा।â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुमा स्वराज : नियम पूरा हो जाने दें। अब नियम क्या है? पहले मंत्री का स्टेटमेंट, उसके बाद चर्चा। चर्चा के बाद मंत्री का रिप्लाई। उसके बाद असंतोा का प्रकटीकरण, अगर संतुट नहीं होते तो। इसलिए मेरा निवेदन है कि स्टेटमेंट हो गया। पहले इन्होंने ध्यानार्काण किया। इन्होंने स्टेटमेंट दे दिया। स्टेटमेंट पर चर्चा हो गई। अब चर्चा का जवाब हो जाए। जवाब से अगर संतुट नहीं होते तो कह दें। तब हम प्रधान मंत्री जी को निवेदन करेंगे ।â€¦ (व्यवधान)पहले जवाब तो सुनिए।â€¦ (व्य वधान)

श्री अरुण कुमार : उन्होंने जवाब में कुछ नहीं कहा है।

श्रीमती सुमा स्वराज : यह आपको कैसे पता है। यह ठीक नहीं है। पहले आप उनका जवाब सुन लें। अगर आप उनके जवाब से संतुट नहीं हैं तो फिर कहें।

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह : जवाब में कुछ भी नहीं है।

श्रीमती सुमा स्वराज : आपने वक्तव्य सुना है, जवाब नहीं सुना। आप पहले जवाब की प्रक्रिया तो पूरी होने दें।

श्रीमती कान्ति सिंह : उनके जवाब में लाचारी है।

श्रीमती सुमा स्वराज : कोई लाचारी नहीं है।

श्रीमती कान्ति सिंह : आप प्रोसिडिंग में देख लें। पहले उनको जवाब तो देने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मैंने आपके आने से पहले यही कहा था।

श्रीमती सुमा स्वराज : इनका जवाब होने दें।

श्री अरुण कुमार : हम मंत्री जी के जवाब से पूर्णतः असंतुट हैं।

श्रीमती सुमा स्वराज : यह तो जवाब आने के बाद निर्णय करेंगे।

डॉ. विजय कुमार मल्होत्रा : बिना जवाब के ही असंतोा व्यक्त कर रहे हैं।

श्रीमती सुमा स्वराज : पहले जवाब सुनिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : मूल प्रश्न के बारे में एक वाक्य भी इनके जवाब में नहीं आया।

श्रीमती सुमा स्वराज : क्या आपने जवाब देख लिया, पहले जवाब तो सुनिए। जवाब आने के बाद संतुट न हों तो फिर कहें।â€¦ (व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : स्टेटमेंट सुना है, जवाब भी सुना है।

उपाध्यक्ष महोदय : पूरा करने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री जी ने जैसा कहा है कि मंत्री जी के जवाब से अगर आपको सैटिसफैक्शन नहीं होती

तो उसके बाद क्या करना है, क्या नहीं करना है, इस पर सोचा जा सकता है। लेकिन उन्हें एक मौका तो देना चाहिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : आपने संसदीय कार्य मंत्री जी सुना, अब हमारी भी सुन लें और फिर निर्णय करें।

उपाध्यक्ष महोदय : सबसे पहले कालिंग अटेंशन डिस्पोजल होना चाहिए, उसके लिए पी.एम.बी. के टाइम में एंक्रोच करना पड़ेगा। Is it the sense of the House to extend the time for this item?

श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव : नो, नो।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम एक निवेदन करना चाहते हैं।

श्री रघुनाथ झा : आप प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस को शुरू कराएं।

उपाध्यक्ष महोदय : समय की बात करें, we are not entitled to proceed like this.

श्री राम विलास पासवान : सुामा जी ने कहा है कि मंत्री जी के जवाब से अगर संतुट नहीं हैं तो प्रधान मंत्री जी से वह आग्रह करेंगी। यहां दोनों पक्ष के लोग मंत्री जी के जवाब से संतुट नहीं हैं।â€¦ (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : अभी जवाब नहीं दिया गया है।

श्री राम विलास पासवान : जवाब है।

उपाध्यक्ष महोदय : वह स्टेटमेंट था।

श्री राम विलास पासवान : आप प्रधान मंत्री जी से जवाब दिलाएं और भविय के लिए इस पर रूलिंग दें कि यह मंत्री जी के नाम से जाता है, राज्य मंत्री के नाम से नहीं जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री जी ने स्पीकर साहब को यह लैटर लिखा है। उसमें कहा है कि यहां प्लानिंग का काम मेरे सहयोगी मुखर्जी देखेंगे और अध्यक्ष महोदय ने उसको हां करके यह किया है। फिर भी संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि अगर उनके जवाब से संतुटि नहीं होगी, तो प्रधान मंत्री जी के बारे में भी सोचा जा सकता है।

â€¦ (व्यवधान)

श्रीमती सुामा स्वराज : जब ये संतुट नहीं होंगे, तब सोचेंगे। पहले आप मंत्री जी को तो सुन लें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : उपाध्यक्ष जी, हम एक निवेदन करना चाहते हैं। संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह कहा है कि कि मंत्री जी को सुन लें। हम आपके माध्यम से उनको निवेदन करना चाहते हैं कि इसके पहले भी एक बार ऐसा ही सवाल उठा था। उस समय वसुंधरा राजे जी ने उत्तर दिया था। प्रधान मंत्री जी जब यहां आए तो कहा कि आप नहीं थे, उस समय उन्होंने पूछा कि किसने उत्तर दिया तो कहा गया कि वसुंधरा राजे जी ने दिया है। उस समय उन्होंने कहा था, नहीं, नहीं। इस मामले में या तो वित्त मंत्री को उत्तर देना चाहिए या स्वयं मैं रहता। यह हम सभी के सामने सदन में प्रधान मंत्री जी द्वारा कहा हुआ वाक्य है। आज जब यह सवाल आया है तो प्रश्न कुछ है और उत्तर कुछ और है। प्रश्न पूर्व के बारे में है और उत्तर पश्चिम के बारे में है। तो कैसे इन पर यकीन किया जा सकता है। सदन में जुदेव जी का मामला हुआ। जिस समय सवाल उठा था माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं थे। जब सवाल उठा तो सुामा जी ने माननीय प्रधान मंत्री जी को अवगत कराया और माननीय प्रधान मंत्री जी ने सदन में आकर जवाब दिया। आज माननीय प्रधान मंत्री जी यहां नहीं हैं। इनके मंत्री जी ने सवाल को नोट किया है। मंत्री जी और सुामा जी माननीय प्रधान मंत्री जी को बताएं। हमने यह मांग तो नहीं की कि कल जवाब दें। जब माननीय प्रधान मंत्री जी को सुविधा हो, तब जवाब दें। यह हमारी भावनाओं का और प्रदेश का सवाल है। माननीय प्रधान मंत्री जी को जब सुविधा हो, तब जवाब दें, हम स्वीकार करने को तैयार हैं।

श्रीमती सुामा स्वराज : उपाध्यक्ष जी, सदन की भावना से निश्चित ही मैं माननीय प्रधान मंत्री जी को अवगत करा दूंगी। जिस तरह की भावनाएं मैं देख रही हूं, उसमें सदन बंटा हुआ नहीं है। सत्ता पक्ष, विपक्ष और निर्दलीय, सभी लोग एक ही तरह से यह बात बोल रहे हैं। अगर माननीय प्रधान मंत्री जी को सुनने की बात है तो फिर उनकी सुविधा से हम लोग समय तय करेंगे और वे जवाब देंगे।

उपाध्यक्ष महोदय : मगर कॉलिंग-अटेंशन का जो नियम है उसके अनुसार तो इसे अभी डिस्पोज-ऑफ करना है।

श्रीमती सुामा स्वराज : नियम तो ये खुद ही तोड़ रहे हैं, खुद ही कह रहे हैं उसको करिये।

रेल मंत्री (श्री नीतीश कुमार) : उपाध्यक्ष जी, 3.30 बजे पर प्राइवेट मैम्बर बिजनैस लिस्टेड है। जो बिजनैस जहां है वहीं खत्म होना चाहिए। यह हमारी व्यवस्था का प्रश्न है। अगर कॉलिंग-अटेंशन यहीं डिस्पोज ऑफ नहीं हुआ तो इसी रूप में रहेगा। आगे आप कोई डेट निकाल कर उसको डिस्पोज ऑफ करेंगे। आज उसका डिस्पोजल कैसे हो सकता है? 3.30 बजे पर प्राइवेट मैम्बर बिजनैस शुरू हो जाए। जैसा संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि उनकी सुविधा देखकर आगे के दिन इसको लगा सकते हैं। इसमें कोई नियम बाधक नहीं है।

श्री राम विलास पासवान : जिस दिन प्रधान मंत्री जी जवाब दें, उसी दिन लिस्ट ऑफ बिजनैस में लगे।

श्री नीतीश कुमार : 3.30 बजे के बाद तो यह स्थगित हुआ है।

उपाध्यक्ष महोदय : मेरी जानकारी में एक नयी परम्परा हम कायम करना चाहते हैं। We have already encroached upon the time of the Private Members' Business.

SHRI RAMESH CHENNITHALA (MAVELIKARA): Mr. Deputy-Speaker, Sir, what about the Private Members' Business? ...(*Interruptions*)

श्री नीतीश कुमार : 3.30 बजे के बाद हम यह सारा डिस्कशन ईर्रेगुलर कर रहे हैं।

श्रीमती सुमा स्वराज : परम्परा और नियम का समाधान यह है कि माननीय मंत्री जी खड़े हों। उन्हें एक-दो वाक्य जो बोलने हैं, उसके साथ कॉलिंग-अटेंशन डिस्पोज ऑफ हो जाए और *suo motu* स्टेटमेंट माननीय प्रधान मंत्री जी बिहार पैकेज पर आकर कर लें।

श्री राम विलास पासवान : उपाध्यक्ष जी, कॉलिंग-अटेंशन में जवाब पर्सनल होता है लेकिन मिनिस्टर के स्टेटमेंट पर कोई पर्सनल जवाब नहीं होता है। इसलिए यह पर्सनल जवाब के रूप में होगा। इसलिए कॉलिंग-अटेशन रूल में आपको संशोधन करना भी पड़े तो यह चेयर का अधिकार है कि वह कर सकता है। आप इसको करें। लिस्ट ऑफ बिजनैस में इसको दुबारा लाया जाए।

डॉ.लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कि दुबारा कॉलिंग अटेंशन चले।

श्रीमती सुमा स्वराज : दुबारा व्यवस्था इसलिए नहीं हो सकती है कि उसी विाय पर उसी सत्र में â€¦ (व्यवधान)

श्री नीतीश कुमार : चेयर को विशेाधिकार है, डायरेक्शन दे सकते हैं, इसको आप चेंज कर सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : उपाध्यक्ष जी, जो व्यवधान हो रहा है उस पर हम कुछ बोलना चाहते हैं। जैसे माननीय मंत्री महोदया ने अर्ज किया *suo motu* स्टेटमेंट के लिए। संसद सर्वोपरि है, इसको कहने की जरूरत नहीं है। कॉलिंग-अटेंशन में चार मैम्बर नामित थे।

कालिंग एटेंशन में चार सदस्यों के नाम के बाद पांचवें नाम का नियम नहीं है। विशेा परिस्थितियों में चेयर को यह अधिकार है कि माननीय सदस्यों को एक प्रश्न पूछने के लिए मौका दिया गया है और यह आज हुआ है। जहां तक परम्परा के समाधान का सवाल है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह कोई नई परम्परा नहीं है। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर बीजनेस लिया जाना था, आपने सदन से सैंस ले लिया और सदन को यह अधिकार हासिल है।

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं लिया जा सका, आपने लोगों ने छोड़ा ही नहीं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : देखिए, फिर रेल मंत्री जी ने जो कहा है, हम उससे सहमत हैं। आपने सैंस नहीं लिया, तो सैंस ले लिया जाए। संसदीय प्रक्रिया में हम आपके साथ हैं, लेकिन प्रधान मंत्री जी का जवाब हो जाए, लेकिन सुओ-मोटो स्टेंटमेंट नहीं होगा। â€¦ (व्यवधान)

श्री राम विलास पासवान : महोदय, नीतीश जी न बिलकुल सही बात कही है। साढ़े तीन बजे कालिंग एटेंशन चल रहा था और उस समय तक इसका डिसपोजल नहीं हुआ था, मंत्री जी का जवाब नहीं मिला था। साढ़े तीन बजे प्राइवेट मैम्बर बीजनेस शुरु हो जाता है और उस वक्त तक मंत्री जी का जवाब नहीं हुआ था, मतलब यह कि जवाब अधूरा है। इसलिए जवाब के लिए अगली तारीख दे दी जाए।

श्रीमती सुमा स्वराज : आपने ही कहा कि कालिंग एटेंशन का जवाब नहीं हो सकता है, जबकि उसी दिन डिसपोजल होता है। यह भी बताया गया कि चार लोग से ज्यादा लोग बोले हैं। That means, the Calling Attention Motion was virtually converted into a discussion. It is not Calling Attention Motion now. It is no more a Calling Attention Motion because so many speakers have spoken.

MR. DEPUTY-SPEAKER: No, I do not agree with that.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: That means, virtually it has been converted into a discussion.

MR. DEPUTY-SPEAKER: I do not agree with that. We have already listed Calling Attention here. The hon. Speaker said, give chance to three or four Members, as a special case.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: So, as a special case, the Prime Minister will reply.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Now, what I am going to decide is this. First of all, is it the sense of the House that we regularised the timing for whatever transaction we have done till now for this purpose? Let me first of all know that.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

MR. DEPUTY-SPEAKER: Then, I am giving you my findings now. This is not concluded now. The reply to the Calling Attention and its disposal would be done on Monday after the Question Hour.

SHRIMATI SUSHMA SWARAJ: No, it is not the next day. प्रधान मंत्री जी की सुविधा से समय तय कर लिया जाएगा, जिससे चर्चा का वे ज वाब दे दें।

उपाध्यक्ष महोदय : मामला समाप्त हो गया।

Now, the House will take up the Private Members' Business.